निशाने पर भारत

भारत को घेरने में जुटा चीन

सिक्यांग

1962 में अक्साई चिन पर चीन का अवैध कब्जा, आज भी निरंतर सीमा अतिक्रमण
POK में हजारों चीनी सैनिकों की उपस्थिति

अरुणाचल पर दावा, सीमा अतिक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर कूटनीतिक दबाव

तज़ाकिस्तान

पाक अधिकृत कश्मीर

अक्साई चीन

नियंत्रण रेखा

अफगानिस्तान

चीन

सिचुआन

तिब्बत

नाग्कू

ल्हासा

कराकोरम हाइवे

पाकिस्तान

नेपाल

चीन नेपाल मैत्री मार्ग

शिगात्से

यातुंग

काठमांडु

सिक्किम

भूटान

अरुणाचल प्रदेश

ग्वादर बंदरगाह

भारत

बांग्लादेश

युनान

बर्मा

सिक्किम पर चीन का दावा
चुंबी घाटी में घुसपैठ

सीमाएँ जहाँ से चीनी घुसपैठ हो रही है
भारत की भूमि जिस पर चीन दावा करता है
सड़क मार्ग
रेल मार्ग

डेलिन्धा में चीनी मिसाइल बेस

पी.ओ.के. में चीनी सेना

लद्दाख में चीनियों द्वारा पत्थरों पर लिखा 'चीन'

अनुक्रमणिका-

पृष्ठ क्र.

शुभकामना संदेश..... २

संपादकीय..... ३

प्रस्ताव..... ४

प्रस्तावों से संबंधित संदर्भ लेखन -

भारत के चारों ओर चीन का सैन्य व्यूह..... ९

भारत के पड़ोसियों को सम्मोहित करता ड्रैगन..... ११

संवेदनशील क्षेत्रों में चीन को घुसपैठ का मौका दे रही है सरकार..... १४

पूरी दुनिया में चीन के साइबर हमले..... १५

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हो रहा चीन..... १८

भारत सहित दुनिया के पानी पर डाका..... २०

भारत की अर्थव्यवस्था में चीन की सेंध..... २२

क्यों नहीं सुधरता पाकिस्तान ?..... २३

देशी रक्षा तकनीक, रक्षा उत्पादन व रक्षा तैयारियाँ–किस राह पर हैं हम..... २९

रक्षा प्रशासनिक ढाँचा – एक प्रश्न ?..... ३१

राजनैतिक षड़यंत्रों व लचर तंत्र की शिकार आतंकरोधी लड़ाई..... ३१

बंगलादेशी घुसपैठ : भारत के सीमा प्रांतों को निगलने का षड़यंत्र..... ३६

असम का तेजी से होता बंगलादेशीकरण..... ३८

❖❖❖

पूज्य सरसंघचालक मान. मोहन भागवत जी के उद्‌बोधन का सारांश..... ४१

❖❖❖

शुभकामना संदेश

आदरणीय बंधुवर,

सादर नमस्कार,

आंर्तबाह्य पवित्रता, उत्साह और समृद्धि का पर्व दीपावली हम सभी के लिए मंगलमय हो। प्रकाश के इस पर्व से प्रेरणा लेकर हम इस प्रकार अग्रसर हों कि हमारा यह राष्ट्र मानवता के लिए सूर्य बनकर चमके।

आए दिन हो रहे आतंकी हमलों और शत्रुओं की कुचालों से भारतवासियों का मन संतप्त हो रहा है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रवादी ध्येनिष्ठ और सुसंगठित समाज की आवश्यकता है। ऐसा जनमत ही शासकों पर सही पग उठाने का दबाव बना सकता है। भारत का जन–जन जाग उठे, और गतिमान हो। हमारी शुभेच्छाएँ फलित हों, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हुआ –

आपका

शंकर प्रसाद ताम्रकार

प्रांत संघचालक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

महाकोशल प्रांत

तिथि – कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी

युगाब्द – ५११३

विक्रम संवत् – २०६८

संपादकीय

14, 15 व 16 अक्टूबर 2011 को गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी रणनीतिक पहल आवश्यक' यह प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव और प्रस्ताव में जिन बिंदुओं को स्पर्श किया गया है, उनसे संबंधित तथ्यपरक सामग्री पुस्तिका में दी जा रही है।

समस्या ये नहीं है, कि आज हमारे सामने आंतरिक-बाह्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ हैं। समस्या ये है, कि हमें जिस प्रकार से उनका उत्तर देना चाहिए, वैसा दिया नहीं जा रहा है। शत्रु हमारे खंड-खंड करना चाहता है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। हमारे सैनिक भी अपना काम कर रहे हैं, पर क्या शासन, प्रशासन और जनता अपना काम कर रहे हैं ? द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति के बाद आज तक 36 राष्ट्रों की सीमाएँ अथवा सार्वभौमिकता खंडित हुई है। इनमें से 80% का कारण आंतरिक सुरक्षा थी। एक और बात महत्वपूर्ण है, कि वहाँ जनसामान्य यह महसूस करता था कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है, और हम संभाल लेंगे। अर्थात् सामर्थ्य के अभाव के कारण नहीं उदासीनता के कारण ये विघटन हुए हैं। आज जन-जन का एक मुद्दा बन गया है, कि भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। यही भाव राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए बने तो इन समस्याओं से पार पाने में समय नहीं लगेगा। यही इस पुस्तिका का उद्देश्य है।

पुस्तिका में रा.स्व.सं. के पूज्य सरसंघचालक मान. मोहन भागवत जी के विजयादशमी उद्बोधन का सारांश भी दिया गया है। वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में उनका यह उद्बोधन संघ की विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि को प्रकट करता है। दिशाबोध प्रदान करता है।

प्रशांत बाजपेई

अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल, युगाब्द ५११३

१४ - १६ अक्टूबर २०११, गोरखपुर

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रभावी रणनीतिक पहल आवश्यक

अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल देश की सीमाओं पर बढ़ते तनाव, सीमा पार से देश में अलगाववाद व आतंकवाद को बढ़ावा देने की बढ़ती घटनाओं, देश की वायु व सामुद्रिक सीमाओं पर उभरती चुनौतियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र व अंतरिक्ष में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध उभरते खतरों के प्रति सरकार की उपेक्षा के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। इस सन्दर्भ में कार्यकारी मण्डल सुरक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित चुनौतियों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है।

चीन से चुनौतियाँ

चीन भारतीय सीमा पर सैन्य दबाव बनाने के साथ–साथ वहाँ पर बार–बार सीमा का अतिक्रमण करते हुए सैन्य व असैन्य सम्पदा की तोड़ फोड़ एवं सीमा क्षेत्र में नागरिकों को लगातार आतंकित कर रहा है। भारत की सुनियोजित सैन्य घेराबन्दी करने के उद्देश्य से हमारे पड़ौसी देशों में चीन की सैन्य उपस्थिति, वहाँ उसके सैनिक अड्डों का विकास व उनके साथ रणनीतिक साझेदारी को भी गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध सशस्त्रीकरण व वहाँ पर भारत विरोधी आतंकवाद को संरक्षण, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चीन की सैन्य सक्रियता, माओवाद के माध्यम से नेपाल में शासन के सूत्रधार के रूप में उभरने के प्रयत्न एवं बाँग्लादेश, म्याँमा व श्रीलंका में चीनी सैन्य विशेषाज्ञों की उपस्थिति इस घेराबन्दी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

कार्यकारी मण्डल का मानना है कि सीमा पार से देश में आतंकवाद व अलगाववाद को बढ़ावा देने के साथ–साथ पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को चीन का सक्रिय सहयोग देश की एकता व अखण्डता को सीधी चुनौती है। चीन द्वारा अपने साइबर योद्धाओं के माध्यम से देश के संचार व सूचना तंत्र में सेंध लगाने की घटनाएँ एवं देश के विविध संवेदनशील स्थानों के निकट अत्यन्त अल्प निविदा मूल्य पर परियोजनाओं में प्रवेश के माध्यम से अपने गुप्तचर तंत्र का फैलाव भी देश की सुरक्षा के लिये गम्भीर संकट उत्पन्न करने वाला है।

चीन द्वारा 1962 के युद्ध में हस्तगत की गयी देश की 38,000 वर्ग किमी भूमि को वापस लेने के उसी वर्ष के 14 नवम्बर के संसद के संकल्प को भारत सरकार ने तो विस्मृत ही कर दिया

है। दूसरी ओर चीन हमारे देश की 90,000 वर्ग किमी अतिरिक्त भूमि पर और दावा जता रहा है, जिस पर सरकार की प्रतिक्रिया अत्यन्त शिथिल रही है। इन दावों व सीमा क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जैसी आधारभूत संरचनाएँ यथा दूरसंचार, रेल, सड़क व विमानपत्तन आदि की सुविधाएँ चाहिये, उनके विकास के प्रति भी सरकार की घोर उपेक्षा अत्यन्त चिन्तनीय है।

सुरक्षा की दृष्टि से चीन द्वारा एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम लम्बी दूरी के अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों को भारतीय सीमा पर तैनात किया जाना एक गम्भीर चुनौती है। चीन द्वारा उपग्रह भेदी एवं जहाज भेदी प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षण कर लिये गये हैं। उसने 8500 किमी की दूरी तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बेलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र युक्त, परमाणु पनडुब्बिया भी विकसित कर रखी है। इन सभी के प्रभावी प्रतिकार की सामर्थ्य का विकास भारत के लिए अविलम्ब आवश्यक है।

भारतीय बाजारों में चीन के उत्पादों की भरमार से रुग्ण होते भारतीय उद्यमों के साथ–साथ चीन के साथ भारी व्यापार घाटा भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त गम्भीर चुनौती बन कर उभर रहा है। दूरसंचार के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के आगे भारत द्वारा कोई प्रयत्न नहीं करने से आज तीसरी व चौथी पीढ़ी की अर्थात् 3जी व 4जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के सारे साज सामान चीनी ही लगाये जा रहे हैं। यह हमारे सूचना व संचार तंत्र की सुरक्षा के लिये संकट का द्योतक है। विद्युज्जनन संयत्रों सहित अन्य उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी चीन पर बढ़ते अवलम्बन से देश उन सभी क्षेत्रों में स्थायी रूप से चीन पर आश्रित होता जा रहा है।

चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नद व अन्य अनेक नदियों के बहाव को मोड़ने की शुरुआत के विरुद्ध भी कड़ा रुख अपनाते हुए भारत को चीन व तिब्बत से निकलने वाली नदियों के बहाव को मोड़ने से प्रभावित होने वाले सभी देशों यथा बाँग्लादेश, पाकिस्तान, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैण्ड व म्याँमा को साथ लेकर नदी जल के न्यायपूर्ण वितरण के समझौते के लिए चीन को बाध्य करना चाहिए।

पाकिस्तानी कुचक्र

भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां भी चिन्ताजनक हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने सेना के कमाण्डरों को सम्बोधित करते हुए स्वीकार किया है कि सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में विगत कुछ माह के दौरान अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार अकेले कश्मीर की सीमा पर विगत साढ़े चार माह के दौरान छिटपुट फायरिंग या घुसपैठ की 70 घटनाएँ

घटी हैं। पाक सेना में कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव वहां के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर भी एक गम्भीर चुनौती बनता जा रहा है।

विगत दिनों सम्पूर्ण विश्व में आतंकवाद का सरगना माने जाने वाले ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मारा जाना और वहाँ उसकी सपरिवार वर्षों तक रहने की पुष्टि, पाकिस्तानी सेना व आई.एस.आई. के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ गहरे सम्बन्धों को प्रकट करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ओसामा को पकड़ने में मदद करने वाले चिकित्सक को गिरफ्तार कर उसपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है।

पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में हामिद करजई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। अपने आन्तरिक कारणों से अगले वर्ष से आरम्भ करते हुए अमरीकी सेना के वहाँ से हटने की स्थिति में पाकिस्तान वहाँ पुनः भारत विरोधी कट्टरपंथी तालिबान को सत्ता में लाना चाहता है। अफगानिस्तान में ऐसी कोई परिस्थिति भारत के लिए सीधी चुनौती होगी। अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल पाक–अफगानिस्तान क्षेत्र की इन घटनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है।

विगत दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए विस्फोट में एक बार पुनः आई. एस. आई. की संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं। इधर इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण मिल रहे हैं कि माओवादियों को मदद पहुँचाने में आई. एस. आई. का नेटवर्क चीन की मदद कर रहा है। पाक–अफगानिस्तान में सक्रिय अत्यन्त खतरनाक हक्कानी गुट के आई.एस.आई. से सम्बन्ध की बात अब जगजाहिर है। परन्तु इस सारे परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का रवैया अभी भी निष्क्रियता का ही बना हुआ है।

बाँग्लादेश सीमा सम्बन्धी मुद्दे

सितम्बर 2011 में बाँग्लादेश के साथ हुई वार्ता में राष्ट्रीय हितों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। असम व प. बंगाल की कई हजार एकड़ भारतीय भूमि को यह कहकर बाँग्लादेश को सौंपना कि "वहाँ पर उनका अवैध अधिकार पहले से ही है", किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता। भूमि की अदला–बदली में कम भूमि पाकर अधिक भूमि देने की बात विवेकहीन व अस्वीकार्य है। साथ ही ऐसा करने से कूचबिहार व जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में बड़ी संख्या में बाँग्लादेशी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ की जनसांख्यिकी बदल जाने से वहाँ अलगाववाद का संकट बढ़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी वार्ताओं में भारत में अवैध रूप से रह रहे करोड़ों बाँग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की जाती है। कार्यकारी मण्डल की माँग है कि बाँग्लादेश से होने वाले समझौतों में राष्ट्रहित, एकता और क्षेत्रीय अखण्डता के मुद्दों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।

हिन्द महासागर क्षेत्र की चुनौतियाँ

अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल इस बात पर भी चिंतित है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में नये शक्ति समूहों के बीच तीव्र हो रही वर्चस्व की लड़ाई में यह क्षेत्र शीत युद्ध काल के यूरोप जैसा अखाड़ा बन रहा है। हिन्द महासागर क्षेत्र के देश संसाधन सम्पन्न हैं तथा नये शक्ति समीकरणों में रणनीतिक महत्व के स्थान लिये हुए हैं। भारत का सदियों से इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान रहा है। अ.भा.का.म. का मत है कि इस समूचे क्षेत्र के साथ दो हजार वर्षों से चले आ रहे सभ्यतामूलक व सांस्कृतिक सम्बन्धों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

चीन ने अपनी समुद्री शक्ति तथा नौसैनिक गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि की है। इस क्षेत्र में उसकी आक्रामक उपस्थिति तनाव उत्पन्न करने वाली है। दूसरी ओर अमरीका दिएगो गार्सिया के सुदूर क्षेत्र में स्वयं को असहज पाकर इस क्षेत्र में निकटता पूर्वक अपनी पैठ और मजबूत करने के प्रयास में है। वर्ष 2003 में इण्डोनेशिया से ईस्ट टिमोर का अलग होना, अपने पड़ोसी श्रीलंका व लिट्टे का संघर्ष, ताइवान मुद्दा आदि इस क्षेत्र में बड़े शक्ति संघर्ष के द्योतक हैं। इन दो शक्तिओं के बीच वर्चस्व की स्पर्द्धा इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगाड़ कर तनाव बढ़ा रही है।

अ.भा.का.म. का मानना है कि ऐसी परिस्थिति में भारत मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकता। इस क्षेत्र के कई देश भारत को शान्ति व स्थिरता का आश्वासन देने वाली कल्याणकारी शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं।

हमारी सरकार की पूर्वोन्मुख (Look East) नीति को 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। कार्यकारी मण्डल सरकार से आग्रह करता है कि अब इस नीति को कार्य रूप में बदलकर क्षेत्र के सभी देशों से सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ किये जाएँ। हमारी विदेश नीति के उद्देश्य हमारी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरुप होना चाहिए। इस सम्बन्ध में म्याँमा व वियतनाम जैसे देशों के साथ की गयी नयी पहल का कार्यकारी मण्डल स्वागत करता है।

हिन्द महासागर में चीन व उसके सहयोगी देशों के इस युद्धोन्माद का हाल में भारत भी अनुभव कर रहा है। विगत दिनों की दो घटनाएँ उनकी इस प्रकार की अक्खड़ता की परिचायक हैं। पहली वियतनाम के पास दक्षिण चीनी समुद्र में भारत तथा चीनी नौ सेनाओं में तनाव की व दूसरी सिन्धु सागर (अरब सागर) में भारत व पाकिस्तानी युद्धपोतों के बीच की घटना है। ग्वाडर से हम्बनतोटा व चटगाँव से कोको द्वीप तक हिन्द महासागर में बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव हमारी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। हिन्द महासागर में अपनी नौ सैनिक उपस्थिति बढ़ाने के लिये ही चीन ने वहाँ 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉली मेटेलिक सल्फाइड्स के खनन की अनुज्ञा प्राप्त की है।

हमारे सशस्त्र सैन्य बल ऐसे सभी खतरों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे सैन्य बलों ने अपनी इस क्षमता का कई बार प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार द्वारा उन्हे वांछित ढाँचागत व शस्त्रास्त्र आधुनिकीकरण में सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है।

देश की सामान्य जनता में व्यापक रूप से विध्यमान राष्ट्रवादी आकांक्षाओं तथा हमारे राजनीतिक तंत्र के नीतिगत दृष्टिकोण के बीच गहरी खाई है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैज्ञानिक दक्षता, सैन्य क्षमता तथा देशभक्ति का ज्वार है। लेकिन, दुर्भाग्य से इन तत्वों की अभिव्यक्ति सरकार की नीतिगत पहल में दिखाई नहीं पड़ती है।

सुरक्षा सम्बन्धी इन चुनौतियों के चलते अ.भा.कार्यकारी मण्डल सरकार से आग्रह करता है कि वह भारत–तिब्बत सीमा सहित देश की सम्पूर्ण थल सीमा, सामुद्रिक सीमा, वायु सीमा, अंतरिक्ष व समग्र सामुद्रिक क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाए। साथ ही अलगाववाद, आतंकवाद व अवैध घुसपैठ जैसी सभी सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे। कार्यकारी मण्डल की माँग है कि सरकार देश के समक्ष उभरती सभी रक्षा चुनौतियों के प्रतिकार हेतु प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों के विकास के साथ–साथ आर्थिक व उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समग्र स्वावलम्बन के लिये व्यापक प्रयत्न करे। अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल जनता से भी आवाहन करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर निरन्तर सजग रहते हुए सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिये बाध्य करे।

❖❖❖

भारत के चारों ओर चीन का सैन्य व्यूह

भारत को चारों ओर से अपने सैन्य व्यूह में कसने के लिए चीन लंबे समय से काम कर रहा है। जल–थल और नभ तीनों ओर से घेरकर भारत को लाचार बना देना, इस दबाव के दम पर भारत से अपने हितों की पूर्ति करवाते जाना और युद्ध की स्थिति में घातक चोट कर सकना उसका लक्ष्य है।

समुद्र से घात :– एशिया, दक्षिणी चीन समुद्र और हिंद महासागर में शक्ति बनने की आकांक्षा के मद्देनजर चीन अपनी नौसेना और नौसेना के पहुँच क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। इसके लिए उसने हांगकांग से लेकर सूडान तक अपनी नौसेना के लिए ठिकाने तैयार किए हैं। इस घेरेबंदी को 'मोतियों की श्रृंखला' String of Pearls कहा गया। इस श्रृंखला का सूत्र हांगकांग से प्रारंभ होकर मलक्का जलडमरुमध्य (Strait), कोको द्वीप, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, होरमज जलडमरुमध्य, मलक्का जलडमरुमध्य होते हुए सूडान तक जाता है। भारत के लिए यह एक नौसैनिक फंदा है। चीन ने समुद्र में भारत को तीनों ओर से घेरने के लिए बंदरगाहों की एक श्रृंखला विकसित की है।

पड़ोसी बंदरगाहों पर चीनी नौसेना :– इसमें पहला क्रमांक है कोको द्वीप का। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह द्वीप 1994 में बर्मा ने चीन को लीज पर दे दिया। बर्मा और चीन दोनों सरकारें इस विषय पर मौन रहती आयी हैं। चीन ने यहाँ पर अपना नौसैनिक आधार तैयार कर जबर्दस्त सामरिक बढ़त हासिल कर ली। इसी प्रकार बर्मा के सीटवे, क्यूक्फ्यू, हाईंगई और तननथलाई बंदरगाहों पर चीनी नौसेना की उपस्थिति दर्ज होती रही है। भारत के अंडमान निकोबार स्थित मिसाइल साइट्स, हवाई अड्डे, सैनिक और वायुसैनिक संस्थान, मॉनिटरिंग स्टेशन्स और उड़ीसा में चांदीपर स्थित मिसाइल परीक्षण रेंज आदि चीनी नौसेना और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी तंत्र की पहुँच में आ गए हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश के चित्तगांग को चीन गहरे पानी के बंदरगाह के रूप में विकसित कर रहा है। चित्तगांग और बर्मा के अन्य बंदरगाहों को चीन से जोड़ने के लिए रेल और सड़क मार्ग तैयार हो रहे हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने एक नौसैनिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया है। हम्बनटोटा श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति महेन्द्र राजपक्षे का निर्वाचन क्षेत्र भी है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी चीन विकसित कर रहा है।

इस समुद्री घेरे की अगली कड़ी है पाकिस्तान का ग्वादर। अरब की खाड़ी के मुहाने पर हथौड़े की शक्ल का बना हुआ प्राकृतिक स्थान, जो गहरे पानी के बंदरगाह के लिए आदर्श है। चीन

ने इसका विकास अत्याधुनिक नौसैनिक बंदरगाह के रूप में किया है। इससे भारत के परंपरागत तेलमार्ग पर दबाव बढ़ गया है। हिंद महासागर में मेटलिक पॉली सल्फाइड्स के उत्खनन की अनुज्ञा उसने प्राप्त की है। कुल मिलाकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के पाँव जम चुके हैं। चीन अपनी नौसेना की मारक क्षमता का भी निरंतर विस्तार कर रहा है।

नौसैनिक फंदा एक बहुउद्देश्यीय कदम :- चीन की इस योजना का उद्देश्य भारत को उसके पिछवाड़े में उलझाकर सीमित करना तो है ही साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपने अन्य सामरिक और व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। डिएगो गार्सिया में अमेरिकी उपस्थिति चीन की क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में बाधक है। यह चाल चलकर उसने इस क्षेत्र में अपना पैर जमा लिया है। भारत और इस क्षेत्र में अमरीकी गतिविधियों की निगरानी और जासूसी आसान हो गई है। वर्षों से चीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, वो है यहाँ से होकर जाता उसका तेल मार्ग। जो भारतीय नौसेना और डिएगो गार्सिया में उपस्थित अमरीकी नौसैनिक बल के निशाने पर है। चीन का तेल ईरान, सउदी अरब, सूडान, नाइजीरिया व अंगोला से चलकर भारतीय उपमहाद्वीप का चक्कर लगाकर मलक्का जलडमरुमध्य से होकर चीन पहुँचता है, चीन उसे सुरक्षित करना चाहता है। वास्तव में भारत भूमि की समुद्र में बढ़ी हुई जो तिकोनी आकृति है, वह भारत को हिंद महासागर में बहुत मजबूत सामरिक स्थिति प्रदान करती है। इस भूमि की तुलना कभी न डूबने वाले जहाजवाहक पोत (Unsinkeble Aircraft Carrier) से की जाती है। यहाँ भारत से उलझना है, तो भारत की मुख्यभूमि और अण्डमान निकोबार द्वीप, दोनों ओर से हमले झेलने होंगे। चीन के तेलमार्ग के संबंध में कहा जा सकता है, कि भारत का हाथ उसकी तेलधमनी (Artery) के निकट है। भारत को अपनी इस स्थिति को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। चीन इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है।

भारत के पश्चिमोत्तर से घात :- चीन की उपस्थिति पाक के ग्वादर बंदरगाह पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। काराकोरम हाइवे की मरम्मत के नाम पर चीनी सैनिक और सैन्य विशेषज्ञ गिलगिट और बाल्टिस्तान में उपस्थित हैं। काराकोरम हाइवे पाक चीन संबंधों की नयी कड़ी तो है ही, चीन के लिए उसके दक्षिण में स्थित नवोदित राष्ट्रों कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तज़ाकिस्तान से संबंधों को भी नया आयाम देगा। यदि चीन इस मार्ग से अफ्रीका और पश्चिम एशिया से आने वाले तेल की आपूर्ति भी करने लगा तो उसके परंपरागत मार्ग पर भारत के दबाव की स्थिति भी उलट जाएगी। ग्वादर और अक्साई चिन में उसके इलेक्ट्रॉनिक जासूसी केन्द्र कार्यरत हैं।

भारत की उत्तरी सीमा और तिब्बत की ओर से :- भारतीय सीमा के निकट चीन के किंघाई प्रांत (Qinghai Province) में एक नाभिकीय अस्त्र वाहक मिसाइल केन्द्र (Nuclear Missile Base) तैयार हैं, जिसका निशाना भारत है। इसके अतिरिक्त चीन ने नये पाँच पूर्णरूपेण कार्यक्षम हवाई अड्डे (Airbase), एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क और स्वायत्त तिब्बती क्षेत्र में 58,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त चीन इस क्षेत्र में पाँच पुराने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। आधुनिक बनाए जा रहे इन हवाई अड्डों से पहले ही चीन के सुखोई 27UBK और सरवोई MKK लड़ाकू जहाज उड़ान भर रहे हैं।

नवनिर्मित विशाल रेल नेटवर्क ने, चीनी सेना को इस दुर्गम क्षेत्र में तीव्र गति प्रदान की है। आज चीनी सेना की दो डिवीजन (30,000 सैनिक) 36 घंटों में हमारी सीमाओं तक पहुँच सकती है। पहले यह समय 10 दिन था। चीन का मिलिटरी बजट बढ़कर 91.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। चीन किंघई तिब्बत रेलवे (Qinghai Tibet Railway) का विस्तार चिगेज (Xigaze) तक कर रहा है। कशगर (Kashgar) से होटान (Hothan) तक दूसरी रेल लाइन का निर्माण जारी है। नये हवाई अड्डे गोंगर, पांगटा, लिंची, होपिंग और गार गुंसा (Gongar, Pangta, Linchi, Hoping and Gar Gunsa) हैं। मई 2011 में खबरें आई हैं, कि चीन ने इतनी क्षमता विकसित कर ली है, कि वो अपने 5 लाख सैनिकों को तिब्बत से लगी भारत की सीमा तक भेज सकता है, और उन्हें एक महीने तक वहाँ रख सकता है।

भारत के पड़ोसियों को सम्मोहित करता ड्रैगन-

चीन दक्षिण एशिया की सर्वोच्च शक्ति नहीं है, पर बनना चाहता है। उसके लिए उसने दक्षिण एशियाई देशों की विकास की भूख और मूलभूत ढाँचे के विकास हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता को आँका। पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध मदद का लालच दिया, क्योंकि भारत चीन के आक्रामक शक्तिपथ की बाधा है।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए उसने उन देशों के भारत के साथ विवादों का सहारा लिया, और भारत को घेरा। दीर्घसूत्री और बहुआयामी नीतियों पर चलते हुए उसने सामरिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंधी लाभ प्राप्त किए हैं। भारत से सीधे टकराव की तैयारी रखते हुए उसने भारत से सीधा टकराव टालने का रास्ता भी निकाला। ऐसा किया पाकिस्तान की

सैन्य और परमाणु क्षमता विकसित कर, तथा तिब्बत में सशक्त सैन्यतंत्र विकसित कर।

चीन और पाक की मैत्री

पाकिस्तान को वो यह विश्वास भी दिलाने का प्रयास करता रहा है, कि वह उसके लिए अमेरिका का विकल्प हो सकता है। सैन्य उपकरणों का साझा उत्पादन, व्यापारिक समझौते और यहाँ तक कि परमाणु बम भी चीन ने पाक को भेंट किया। 2 मई 2011 को एबटाबाद में ओसामा के मारे जाने के बाद चीन ने पाक वायुसेना को आवश्यक विमान बेचने के मामले में शीघ्रता करने का वचन भी दे दिया है।

पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन के सिक्यांग प्रांत तक काराकोरम हाइवे की मरम्मत और विकास जारी है। गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर जा सकने वाली रेलमार्ग की संभावना का अध्ययन जारी है। पाक के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक कई प्रस्तावों में से चीन ने गिलगिट बाल्टिस्तान और काराकोरम हाइवे को उच्च प्राथमिकता दी है। चीन ने ग्वादर का विकास नौसैनिक बंदरगाह के रूप में किया है, परंतु ग्वादर को वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में भी विकसित करने के पाकी प्रस्ताव को वो महत्व नहीं दे रहा है। साथ ही पाक के ग्वादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने और ग्वादर से चीन के सिक्यांग तक तेल गैस पाइपलाइन बिछाने के भी लंबे समय से लंबित हैं।

स्पष्ट है कि चीन का उद्देश्य भारत पर दबाव बढ़ाना है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन उपलब्ध कराया। चीन यह भी प्रयास कर रहा है कि सैन्य परमाणु शक्ति और उसे ले जाने के साधनों में पाक भारत पर बढ़त हासिल कर ले। गिलगिट बाल्टिस्तान में हजारों चीनी सैनिकों की उपस्थिति अब जगजाहिर है। आतंकवाद के मामले चीन परोक्ष रूप से पाक को पूरा समर्थन दे रहा है। चीन की नीति तय है, कि पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुँचे और पाकिस्तान भारत का सिरदर्द बना रहे। भविष्य में भी वह यही करता रहेगा। ऐसा पाक चीन के हित में है, जो भारत के लिए खतरा बना रहे। चीन पाक का यह गठजोड़ युद्ध के समय भारत को दो ओर से घेरेगा ही, जब शांति है, तब भी यह भारत के लिए गुप्तचर युद्ध के भी दो मोर्चे बनाता है।

नेपाल पर डोरे

नेपाल भी चीन की प्राथमिकता में है। नेपाल को चीन सड़क व रेलमार्ग से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत नेपाल के माध्यम से तिब्बत में अस्थिरता पैदा कर सकता है, यह चीन के ध्या

न में है। नेपाल में माओवादियों की उपस्थिति का लाभ उठाकर वहाँ पैर जमाने का प्रयास चीन कर रहा है। प्रचंड दहल के नेतृत्व में माओवादी नेपाली सेना का अंग बन जाएं तो चीन को भारत के विरुद्ध एक और मोर्चा खोलने की राह तैयार हो सकेगी। चीन की दृष्टि में माओवादी प्रभुत्व वाला नेपाल भारत के विरुद्ध जबर्दस्त मोहरा सिद्ध हो सकता है।

1998 में नेपाल ने अपने सैन्य अधिकारियों तथा सैनिकों को चीन के सैन्य संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजना प्रारंभ कर दिया। 5 अगस्त 2008 को नेपाल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में बोलते हुए नेपाल में चीनी राजदूत झेंग सिआंगलिन (Zheng Xianglin) ने कहा कि नेपाल एक अनुकूल भौगोलिक स्थिति में है और चीन का दक्षिण एशिया में जाने का रास्ता है। स्पष्टतः भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध मजबूत करने की नीति जिसे 'पूर्व की ओर देखना' कहा जाता है, की काट के रूप में चीन ने दक्षिण की ओर देखने की नीति अपनाई है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका और पाकिस्तान आते हैं। ल्हासा से काठमांडू को सड़क व रेल द्वारा जोड़ने के चीनी प्रयास सफल हुए तो भारत की सुरक्षा को गंभीर चुनौती उत्पन्न होगी।

चीन नेपाल में माओवादियों को सत्ता दिलाना चाहता है, उसका एक और कारण है, कि नेपाल के अंदर तिब्बती शरणार्थियों की चीन विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके। तिब्बत में हान लोगों को बसाकर तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बनाने की चीन की नीति का यहाँ विरोध होता आया है। अमेरिकी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त रेडियो फ्री एशिया तिब्बतियों को लक्ष्य कर अनेक कार्यक्रम प्रसारित करता है। स्वाभाविक है, कि चीन सोचता है, कि नेपाल में बसे इन तिब्बती शरणार्थियों का उपयोग भारत और अमेरिका कर सकते हैं। नेपाल में अब तक एक दूसरा नया खिलाड़ी चीन सामने है, जो भारत को कड़ी टक्कर दे रहा है।

बंग्लादेश में चीन

बांग्लादेश चीन की तीसरी वरीयता है। प्रधानमंत्री शेखहसीना भारत से अपनी मित्रता के बावजूद अपनी पूर्ववर्ती बेगम खालिदा जिया की चीन संबंधी नीति को जारी रखे हैं, और बांग्लादेश–चीन मैत्री परवान चढ़ रही है। उनकी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश में तेलगैस खनन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वो चीन से चित्तगांग को आधुनिक गहरे पानी के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए भी सहायता ले रही हैं। भारत को उन्होंने आश्वासन दिया है, कि चीन की सहायता से विकसित इस बंदरगाह का उपयोग भारत भी कर सकेगा।

बर्मा और श्रीलंका ने भी चीन के साथ ऐसे समझौते किए हैं, परंतु उन्होंने भारत को

तेलगैस खनन का समान अधिकार भी दिया है, पर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ जनसामान्य में प्रभावी इस्लामी कट्टरपंथी भारत विरोधी उन्माद को भड़काते रहे हैं। चीन के युनान से बर्मा होते हुए बांग्लादेश को रेल से जोड़ने की योजना भी विचाराधीन है। बर्मा और चीन के मध्य तेलगैस पाइप लाइन बनाई जा रही है, इसी से बांग्लादेश को जोड़ने पर भी विचार जारी है। 13 जून 2010 को चीन के उपराष्ट्रपति की जिन्पिंग ने ढाका में कहा कि वे चित्तगांग में गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण तथा बांग्लादेश के प्रथम उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायता करना चाहते हैं।

दक्षिण में दस्तक

श्रीलंका चौथी वरीयता प्राप्त दक्षिण एशियाई देश है। महेन्द्र राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका ने 50% वित्तीय सहायता अकेले चीन से प्राप्त की। चीन यहाँ हम्बनटोटा बंदरगाह मथ्थला एयरपोर्ट हम्बनटोटा और कोलंबो–कट्नायके एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहा है। रेल्वे के आधुनिकीकरण के लिए भी समझौता हुआ है। हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास नौसैनिक उपयोग हेतु किया गया है, जिसका उपयोग चीन व श्रीलंका की नौसेना करने वाले हैं, परंतु यहाँ पर वाणिज्यिक बंदरगाह निर्माण के श्रीलंका के प्रस्ताव में चीन रूचि नहीं दिखा रहा है। हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका ने भारत सरकार से बात की थी परंतु उत्साहजनक उत्तर न मिलने पर श्रीलंका सरकार चीन की ओर मुड़ी और चीन ने मौके को झपट लिया।

❖ ❖ ❖

संवेदनशील क्षेत्रों में चीन को घुसपैठ का मौका दे रही है सरकार

भारत सरकार ने 14 सितंबर 2011 को चीन की निवेशक और इंजीनियरिंग कंपनियों को न्यौता दिया कि ''वे प्रमुख मार्गों के निर्माण में शामिल होने आगे आएं, यहाँ तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी।'' यह बात राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री श्री कमलनाथ ने चीनी अधिकारियों से कही। उन्होंने चीनी अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में सड़क निर्माण परियोजनाओं में चीन के शामिल होने से कोई परहेज नहीं है। चीन को एक संयुक्त उपक्रम का प्रोजेक्ट दे भी दिया गया॥

पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्यों पर दबी कुचली असहमति जताने वाली भारत सरकार अपने इस कदम से चीन और दुनिया को क्या संदेश देने जा रही है, यह तो कोई भी समझ सकता है। भारत के नैतिक बल को कमजोर करने वाला यह कदम

पूर्वांचल और जम्मूकश्मीर की सुरक्षा और स्थिरता को भी प्रभावित करने वाला है।

श्री कमलनाथ ने सफाई दी है कि ''चिंता करने की कोई बात नहीं है,क्योंकि चीन इसमें निवेश और तकनीकि योगदान के लिए आएगा।'' लेकिन क्या निवेश और तकनीक आसमान में उड़कर यहाँ पहुँचेगा ? क्या प्रशिक्षित श्रमिक के रूप में चीनी यहाँ नहीं आऐंगे ?

पूर्वांचल में सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के निर्माण कार्यों का चीन विरोध करता आया है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर वह अपना दावा जताता है। ऐसे में मूलभूत ढाँचे के निर्माण में चीन के साथ संयुक्त उपक्रम चीन के सामने क्या सिद्ध कर रहा है ? चीन को दी जा रही ये रिश्वत चीन के दावे को ही मजबूती प्रदान करेगी। विडंबना यह है कि 14 सितंबर को भारत सरकार की इस उदार पेशकश के 24 घंटों के अंदर ही चीन ने भारत को चेतावनी जारी कर दी कि भारत वियतनाम के साथ दक्षिणी चीन समुद्र में तेल और गैस खोजने के किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर ना करे।

ONGC द्वारा ऐसा किये जाने के प्रयासों के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इसे चीन की समुद्री सीमा बताते हुए सभी देशों को इससे दूर रहने की सलाह दी। प्रवक्ता जिआंग यू ने उम्मीद जताई कि बाहरी देश इस विवाद से दूर रहेंगे।

मजे की बात यह है कि चीन द्वारा जिस समुद्री क्षेत्र पर दावा जताया जा रहा है, उस पर वियतनाम सहित 10 देशों का दावा है। वहीं दूसरी ओर पाक अधिकृत कश्मीर में वह पाकिस्तान के साथ मिलकर सड़क रेल और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी संबंधी परियोजनाओं के निर्माण में लगा है। क्या हम भारत सरकार से आशा कर सकते हैं, कि वह कम से कम भारत का पक्ष रखने का साहस जुटा सकेगी ?

❖ ❖ ❖

पूरी दुनिया में चीन के सायबर हमले

चीन की रक्षा तैयारियाँ उसके वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर चल रही हैं। उसकी तैयारियों में रूस और अमेरिका के भय की छाया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अमेरिका और रूस जहाँ वैश्विक दखल रखते हैं, वहीं चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी पूरी तरह धाक नहीं जमा पाया है। परंपरागत सैन्य हार्डवेयर में वह अमेरिका व रूस से एक से तीन पीढ़ी तक पीछे है। ऐसे में सायबर युद्ध की तैयारियाँ उसने काफी पहले से ही प्रारंभ कर दी हैं, ताकि महाशक्तियों से प्रतिस्पर्धा की जा सके।

वास्तव में खाड़ी संकट के दौरान 17 जनवरी 1991 को जब ईराक पर हमला शुरु हुआ तो पूरी दुनिया सहित चीन की आँखें भी उस पर लगी हुई थीं। युद्ध के परिणामों ने चीन के रणनीतिकारों को जबर्दस्त झटका दिया जब उन्होंने देखा कि तकनीक के आधार पर कैसे बिना अपने सैनिक गंवाए अमेरिका और उसके मित्र देशों ने ईराक की सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। युद्ध का परिणाम ईराक के लिए इतना विनाशकारी था, कि प्रत्येक महत्वाकांक्षी देश चौकन्ना हो गया। तब चीन ने तय किया कि उसके संपूर्ण सैन्य तंत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। सायबर युद्ध की चीन की तैयारियाँ उसकी नीति का हिस्सा हैं।

सायबर युद्ध के माध्यम से क्या किया जा सकता है, यह हमारे लिए समझना आवश्यक है। इसे हम कुछ प्रचलित शब्दों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं।

सायबर सैनिक सर्वेक्षण और सायबर हमला– (Cyber Recommandance and Attack) - सायबर हमले में इंटरनेट के माध्यम से हैकिंग कर दुश्मन को नुकसान पहुँचाया जाता है। इसमें कम्प्यूटर को भौतिक क्षति, फाइल्स को डिलीट करना या रिराइट करना, किसी नेटवर्क को नष्ट करना और ऑफलाइन सर्विस शामिल हैं। सायबर सैन्य सर्वेक्षण में डाटा एकत्रित करना आता है। इसमें तकनीक स्थानांतरण और जासूसी भी शामिल है। साथ ही किसी सैन्य दस्ते की स्थिति, तैयारी और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। कई बार हैकर्स पहले सायबर सर्वेक्षण करते हैं और फिर हमला। सेनाओं का उच्च संचार तंत्र, लड़ाई के मैदान का सूचना तंत्र, गुप्त जानकारियाँ, मीडिया युद्ध सबकुछ सायबर युद्ध के अंतर्गत आता है। **हैकिंग के माध्यम से बहुत थोड़े खर्च में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसे पकड़ना और इससे बचना मुश्किल है। आप अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से बच सकते हैं, और भौगोलिक दूरी इसमें मायने नहीं रखती।**

सायबर युद्ध का सबसे सामान्य तरीका सुरक्षा तंत्र की हैकिंग है। किसी कमजोरी का पता लगाकर उसके माध्यम से शत्रु के तंत्र में पहुँचना सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट (Security exploit) कहलाता है। यह एक छोटा सॉफ्टवेयर, डाटा या कमांड होता है, जो दुश्मन के कम्प्यूटर को, या कम्प्यूटर के किसी विशेष सॉफ्टवेयर को अथवा किसी उपकरण के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र को नियंत्रित कर उसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। इसलिए हैकर्स जिनको निशाना बनाना चाहते हैं, उनकी कमजोरियों (Security exploits) को ढूँढ़ते रहते हैं। कई हैकर्स इन Security exploits को ब्लैक मार्केट में बेचते भी हैं। 2006 में चीन ने ताईवान पर ऐसे 13 हमले किए, जिन्हें ठीक करने में (to

develop patches) माइक्रोसॉफ्ट को 178 दिन लगे। युद्ध के समय ऐसे हमले विरोधियों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। सायबर युद्ध का एक और आयाम हमलावर द्वारा अपनी पहचान छुपाना है। यह आज संभव है, कि A आप पर हमला करे परंतु आपको प्रमाण B या C के विरुद्ध मिलें। हैकिंग की दुनिया में ये खेल चलते रहते हैं। ये एक ऐसी आभासी (Virtual) दुनिया है, जिसका आज यथार्थ पर बहुत गहरा प्रभाव है।

सायबर युद्ध में चीन की बढ़त

टाइटन रेन (Titan Rain)– सायबर युद्ध के महत्व और संभावित परिणामों को अच्छी तरह समझने का बहुत अच्छा उदाहरण टाइटन रेन है। यह नाम चीन द्वारा वर्ष 2003 से 2006 के बीच अमेरिकी रक्षा संस्थानों पर क्रमबद्ध और समन्वित हमलों की श्रंखला को दिया गया है। इन हमलों की व्यापकता इतनी थी कि इन्होंने अमेरिका रक्षा और एयरोस्पेस संस्थानों, सॅन्डिया नेशनल लैब, लॉकहीड मार्टिन, रेडस्टोन आर्सेनल, रक्षा विभाग और यहाँ तक कि नासा (NASA) को अपने हमले की जद में लिया और महत्वपूर्णस सैन्य डाटा चुराया। इससे अमेरिका के कई रक्षा प्रयोगों तथा उसके सुरक्षा तंत्र की कई कमजोरियों की जानकारियाँ चीन के हाथ लगीं। इसमें अंतरिक्ष संबंधी तकनीक और अमेरिका के मंगल ग्रह अभियान की जानकारी भी शामिल है। इन हमलों की प्रकृति और क्रियाविधि को समझने के लिए एक तथ्य बहुत उपयोगी है, कि चीन में बैठे हुए 6 से 30 हैकर्स के समूह ने 30 मिनिट के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटर्स को अपने नियंत्रण में ले लिया, उन कम्प्यूटर्स में रखी सारी जानकारी को कॉपी करके साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग के उन कम्प्यूटर्स को भेजा जिन पर उन्होंने पहले से नियंत्रण (हैक) कर रखा था (ताकि चीन पर आरोप न लग सके) और फिर वहाँ से यह डाटा चीन के गुआंगदांग प्रांत में अपने ठिकानों पर रखे कम्प्यूटर्स तक पहुँचा दिया।

भारत पर निरंतर हो रहे हैं सायबर हमले

भारत पर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 मई 2008 को लिखा कि भारत पर चीन लगभग रोज सायबर हमले कर रहा है, और भारत सरकार मौन है। सरकारी सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि ये हमले बहुत उन्नत और संपूर्णता लिए हुए हैं। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकट रूप से वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, कि ''हैकिंग एक दैनिक घटना है, और विश्व के अनेक हिस्सों से ऐसे हमले होते रहते हैं।'' परंतु अकेले में वे स्वीकारते हैं, कि चीन की ओर से खतरा ज्यादा वास्तविक है। पर्दे के पीछे कितना नुकसान हो चुका है यह कहना कठिन है, क्योंकि इसकी अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना तय है, कि ये हमले लगातार जारी हैं, और इनके

निशाने पर भारतीय सुरक्षा संस्थान, सरकारी सूचना तंत्र, NIC, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से लेकर निजी साइट्स तक हैं। भारत को इस दिशा में दूर तक चलना है।

❖ ❖ ❖

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हो रहा है चीन

11 जनवरी 2007 चीन का एक मौसम संवेदी उपग्रह हमेशा की तरह चक्कर लगा रहा था। 7 वर्ष पूर्व छोड़ा गया ये उपग्रह अब बेकार हो चुका था, परंतु जमीन पर उपस्थित अपने नियंत्रण केन्द्र को अपनी स्थिति की सूचना निरंतर भेज रहा था। जब यह उपग्रह दक्षिणी चीन के ऊपर से गुजर रहा था, तभी 6 फीट लंबे इस उपग्रह से (जो कि अंतरिक्ष में बहुत ही छोटा आकार कहा जाएगा) 18,000 मील प्रतिघंटा की रफ्तार से एक मिसाइल आकर टकराया और यह उपग्रह बारीक मलबे का धुंध में बदल गया। चीन के इस उपग्रह को नष्ट करने वाली मिसाइल चीनी मिसाइल ही थी, जिसने चीन के सिचुआन प्रांत के मिसाइल रेंज से उड़ान भरी थी। यह बहुचरणीय ठोस ईंधन (Multi stage, solid fuel missile topped with a kinetic kill vehical) मिसाइल थी, जिसने तेजी से अंतरिक्ष में घूमते एक उपग्रह पर अचूक निशाना लगाया था। इस प्रयोग ने विश्व में हलचल मचा दी। अब तक यह क्षमता अमेरिका व रूस के ही पास थी। चीन इसके पहले अंतरिक्ष में मानव भेज चुका था, और अंर्तमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स (ICBMS) विकसित कर चुका था, अब उसने अपनी अंतरिक्ष युद्ध क्षमता का आक्रामक प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया था। वो भी तब जब उस पर लंबे समय से इस तरह के प्रयोग ना करने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा था। चीन ने अंतरिक्ष युद्ध की उस क्षमता का परिचय दे दिया था जो बिरले देशों को ही हासिल है। चीन के इस प्रयोग के बाद भारत ने इस दिशा में बढ़ने के अपने इरादों की घोषणा की। और इजराइल में बहस शुरु हुई कि चूँकि चीन अपनी मिसाइल तकनीक ईरान को बेचता आया है, अतः इजराइल को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। युद्धकाल में जहाँ यह चीन के विरोधियों के लिए ऐसा भयंकर अस्त्र है, जो उनकी संचार व्यवस्था को ठप्प कर सकता है, वहीं शांतिकाल में इस प्रयोग से उत्पन्न हुआ मलबा अंतरिक्षयानों और उपग्रहों के लिए भयंकर मुसीबत पैदा करने वाला है।

चीन की सेना का चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सीधा दखल है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला यह पाँचवा देश था। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला और सैटेलाईट रोधी क्षमता प्राप्त करने वाला तीसरा देश था। अंतरिक्ष में मानव भेजने में उसने रूस से सहयोग प्राप्त किया। आज

उसके पास अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता है, जिसका सैन्य उपयोग भी किया जा सकता है। संभावित अंतरिक्ष यात्री (चीन की प्रचलित भाषा में tainknouts) चीनी वायुसेना से चुने जाते हैं, और चीन की सेना (PLA) तय करती है, कि कौन से ऐसे अंतरिक्ष संबंधी उपकरण अथवा तकनीक हैं, जिनका सैन्य उपयोग संभव है। चीन के ज्यादातर उपग्रहों की रचना इस प्रकार से की गई है, कि उनका व्यापारिक और सैन्य उपयोग, दोनों किया जा सके। उसके उपग्रहों में भूमि और समुद्र का सर्वेक्षण करने वाले, आपदा व मौसम प्रबंधन क्षमता वाले और उच्च रिजॉल्यूशन (High Resolution) क्षमता वाले दिन और रात में देख सकने वाले ऐसे उपग्रह शामिल हैं, जो अंतरिक्ष से धरती पर पड़ी 10 सेंटीमीटर की वस्तु को पहचान सकते हैं। चीन इन उपग्रहों को युद्ध के वातावरण में ढालने और नियंत्रण करने की क्षमता का विकास करने में लगा है। एक और विशेष बात यह है कि चीन दूसरे देशों के उपग्रहों को ढूँढ़ने और पहचानने की तकनीक का विकास कर रहा है, ये सभी बातें उसके इरादों को स्पष्ट कर देती हैं। सारी तकनीक का विकास करते हुए चीन की दो प्रतिबद्धताएँ हैं एक रूस और अमेरिका की तुलना में यह क्षमताएँ तुलनात्मक रूप से कम खर्च पर प्राप्त करना और दूसरा तकनीक के क्षेत्र में स्वावलंबी होने का निरंतर प्रयास करना।

इसी प्रकार जुलाई 2008 में खबर आई कि चीन ने पानी के जहाज नष्ट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल (Antiship missiles) विकसित कर ली है। इन्हें सिज़लर (Sizzler) मिसाइल कहा गया। इनकी विशेषता यह थी कि जहाँ ज्यादातर Antiship क्रूज मिसाइल्स ध्वनि से थोड़ा कम रफ्तार पर चलती हैं और सीधी चलती हैं जिससे उन्हें लक्ष्य कर नष्ट करना (Track and Target) आसान होता है, वहीं दूसरी ओर चीन की सिज़लर मिसाइल ध्वनि से थोड़ा कम रफ्तार पर छूटती है और लक्ष्य से 10 नॉटिकल मील (नॉटिकल माइल – समुद्र में दूरी नापने की इकाई) की दूरी पर इसमें से वॉरहेड (बम) बाहर लक्ष्य की ओर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, जो जल्दी ही ध्वनि की तीन गुना रफ्तार पकड़ लेता है, और लक्ष्य से टकरा जाता है। यह मिसाइल पानी की सतह अधिकतम 10 मीटर ऊपर उड़ती है। लक्ष्य से टकराने के पहले यह अत्यंत कुशलतापूर्वक मुड़ सकती है।

चीन अंर्तमहाद्वीपीय मिसाइल विकसित कर चुका है, और राडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ बमवर्षक विकसित करने में लगा हुआ है। इस तकनीक के विकास के लिए चीन ने राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिचय तो दिया ही है, साथ ही आवश्यक तकनीक को चुराने से भी उसे परहेज नहीं रहा है।

आज चीन मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने अथवा कहीं से भी प्राप्त

करने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहा है। 2007 में रूस की रॉकेट और अंतरिक्ष तकनीक के प्रमुख को चीन को संवेदनशील जानकारी बेचने के आरोप में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार बेल्जियम में पकड़े गए चीनी एजेंट ने सारे यूरोप में सैकड़ों चीनी जासूसों के होने की बात स्वीकार की है। एक और घटना में फ्रांस ऑटोमेटिव उत्पादक वैलिओ (Valeo) में डाटाबेस चुराते हुए चीनी एजेंट गिरफ्तार हुआ। स्वीडन में एक चीनी अतिथि शोधार्थी (Guest Researcher) को अप्रकाशित, पेटेंट न किया हुआ डाटाबेस चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलिया में चीनी राजनयिक चेन योंगलिन को ऐसे ही आरोपों में ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया में 1000 के लगभग चीनी जासूस कार्य कर रहे हैं। चीन साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से आवश्यक तकनीक हासिल करने में लगा है। भविष्य के युद्ध तकनीक आधारित होंगे, यह ध्यान में रखकर उसका अभियान जारी है।

❖ ❖ ❖

भारत सहित दुनिया के पानी पर डाका

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बाँध बनाए जाने के समाचार काफी समय से आ रहे हैं। जल संसाधन और सामरिक दोनों ही दृष्टि से यह चेतावनी है। चीन ऐसा सिर्फ भारत के साथ ही नहीं कर रहा है। उसके लगभग सभी पड़ोसी देशों से उसके जल विवाद हैं। यही इस समस्या के समाधान की कुंजी भी है। बात को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ जानकारियाँ होना आवश्यक हैं।

जो लोग दक्षिणी चीन सागर में चल रहे विवाद से परिचित हैं, वे जानते हैं कि चीन दुर्लभ खनिजों और जीवाश्मीय ईंधन पर एकाधिकार के लिए नित नये दावे कर रहा है, हेकड़ी दिखा रहा है, और धमकी दे रहा है। वह जापान और ताइवान के समुद्री क्षेत्रों में भी निरंतर घुसपैठ कर रहा है। पिछले कुछ समय से चीन ने नदियों के जल को भी एक हथियार के रूप में उपयोग करना शुरु कर दिया। चीन से अपनी सीमाएँ साझा करने वाले सभी देश चिंतित हैं। चीन में से निकल कर दूसरे देशों में जाने वाली नदियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। ये नदियाँ भारत, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, रूस आदि देशों में जाती हैं। वर्तमान चीन की तमाम बड़ी नदियाँ उन क्षेत्रों से निकलती हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, और ये चीन के भू-भाग का 60% है। ऐसे भू-भाग में तिब्बत प्रमुख है।

जल के बंटवारे को संस्थागत रूप देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को चीन विफल करता आया है। दुनिया के किसी भी देश में चीन जितने बाँध नहीं हैं। विश्व के 50 हजार बड़े बाँधों में से आधे

चीन में ही हैं। विश्व का सबसे बड़ा बाँध 3 जॉर्जेस भी इनमें से है। इसके बाद भी चीन नदियों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को बदलकर उन्हें अपने एकाधिकार में लाने के प्रयास में लगा हुआ है। ब्रह्मपुत्र, मैकांग, सतवीन, अरुण, अयुर, इरटिश इली जैसी नदियों पर चीन बड़े–बड़े बाँध बना रहा है, और वो देश जहाँ से होकर ये नदियाँ बहती हैं, चिंतित हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम आदि शामिल हैं।

मेकांग नदी पर एफिल टॉवर से भी ऊँचा बना नवीनतम बाँध अकेला ही इतनी ऊर्जा पैदा करता है जितनी इस नदी पर बाँध बनाकर अन्य दूसरे देश कर रहे हैं। मेकांग चीन से निकलकर बर्मा, लाओस, थाईलैण्ड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। चीन के सरकारी पनबिजली उद्योग ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें निर्माण के लिए स्वीकृत नये बाँधों की सूची है। इसमें ब्रह्मपुत्र पर मेटोग में बनने वाले बाँध का भी जिक्र है। यह चीन में बने विश्व के सबसे बड़े 18300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले 3 जॉर्जेस से दोगुना बड़ा होगा। इससे भारत में करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। अगले दशक में विकासशील देशों में बनने वाले नये बाँधों में आधे चीन में बनेंगे।

विदेशों में भी चीन बाँध बनाने में अग्रणी है। पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान में और बर्मा के समस्याग्रस्त शान और कचिंग प्रांतों में बाँध बनाकर चीन नये विवाद खड़े कर रहा है। इन परियोजनाओं में चीन जो गोपनीयता बरत रहा है उसने विश्व समुदाय को चिंतित कर दिया है।

नदियों पर एकाधिकार जमाने वाली चीन की नीतियों के कारण इन अंतर्राष्ट्रीय नदियों के चीन की आंतरिक नदियों के रूप में बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। जिसके कारण चीन अपने अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारे संबंधी विवादों में उलझ गया है। चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारे पर संधि करने का इच्छुक नहीं है। 1997 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय जल नीति पर साझा संसाधन के प्रस्ताव का चीन ने विरोध किया था। यह मात्र संयोग नहीं है, कि जहाँ एक ओर दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के बीच जल बंटवारा संधियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की किसी भी पड़ोसी के साथ ऐसी संधियाँ नहीं हैं। चीन की इस दादागिरी से समूचे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, ऐसे प्रभावित देशों के साथ भारत सरकार को संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि परंपरागत रिहायशी इलाकों में चीन के द्वारा बनाये जा रहे विशाल बाँधों से चीनी शासन के विरुद्ध स्थानीय लोगों में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया है। इसमें तिब्बत, सिक्यांग और इनर मंगोलिया शामिल हैं। जैसा कि इस लेख के शुरु में कहा गया था कि समस्या में ही उसका समाधान निहित है।

❖ ❖ ❖

चीन विश्व का पहला देश है जिसने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड के खनन की अनुज्ञा प्राप्त की है। 7 **मई** 2010 को चीन ने इसका आवेदन दिया था। **जुलाई** 2011 में उसे यह अनुमति प्राप्त हो गई। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में इस तरह के खनन का अग्रणी देश रहा था, और यह भारत के लिए एक मौका हाथ से चले जाने की बात है। इस खनन से भारत को ताँबा, कोबाल्ट और मैग्नीज, का विशाल भंडार प्राप्त होता परंतु भारत सरकार पहल करने चूक गई। आर्थिक नुकसान के अलावा यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इससे चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में निर्बाध आने जाने का अवसर प्राप्त हो गया है। समुद्र क्षेत्र में अपनी बढ़त साबित करने का मौका तो उसे मिला ही, हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी गतिविधियों पर नज़र रखने और जासूसी करने का मौका भी उसे मिल गया है। इसे **भारत सरकार** की एक असफलता के रूप में देखा जा रहा है। 2 **अगस्त** 2011 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) को इस विषय पर **नीतिपत्र** (Policy Paper) तैयार करने का काम दिया गया है।

❖ ❖ ❖

भारत की अर्थव्यवस्था में चीन की सेंध-

चीनी माल आज छोटे से छोटे शहर कस्बे तक पहुँच चुका है। इसमें से बहुतांश स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। चीनी माल हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। कारण है चीन की एकतरफा व्यापार नीति, और हमारी ओर से नीति का अभाव।

सस्ता चीनी श्रम, घटिया कच्चा माल और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की कीमत पर मुनाफा ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो चीनी माल को सस्ता बनाता है। डीलर्स के लिए अधिक लाभप्रद होने के कारण चीनी माल हर जगह उपलब्ध है। इससे स्थानीय उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। चीनी कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, पाइप, दूध पाउडर, खाद्य पदार्थ, पेय, जूते, घड़ी, मोबाइल, पेन, साबुन, तेल, पाउडर हमारे बाजार में पहुँच चुके हैं। हद तो यह हो चुकी है कि राखियाँ, होली के रंग गुलाल और गणेश प्रतिमाएँ तक चीन से बनकर भारत के बाजारों तक पहुँच रही हैं। परिणामस्वरूप स्थानीय उद्योग जो भारत के उत्पादन का 30 से 40% है, और रोजगार में उसके योगदान का प्रतिशत 50 से अधिक है, बरबाद हो रहे हैं। मुंबई के निकट भिवंडी व ठाणे के औद्योगिक क्षेत्र में 60% उद्योग बंद हो गए हैं। बहुत सारी लघु उद्योग इकाइयों ने उत्पादन बंद कर दिया है, और चीनी माल मँगवाकर उस पर अपना लेबल लगाकर बेच रही हैं। बहुत सारा चीनी माल चोरी छिपे भी

भारत आ रहा है। चीन समुद्र के रास्ते नकली दवाइयाँ भारत भेज रहा है। मई 2009 में चेन्नई बंदरगाह पर नकली दवाइयों के तीन कन्साइनमेंट पकड़े गए। यह मामला अपने आप में काफी गंभीर है। कुछ बातें गौर करने योग्य हैं :–

(1) भारत का दवा (फार्मा) उद्योग 12 बिलियन डॉलर का है, जो निर्यात द्वारा 40% राजस्व उत्पन्न करता है।

(2) भारत के दवा उद्योग को खत्म करने के लिए चीन ने दुहरी नीति बनाई–

(अ) भारत में नकली दवा भेजकर भारत के दवा उद्योग को नुकसान पहुँचाना।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय लेबल लगाकर नकली दवाओं की आपूर्ति करना।

CDSCO ने भारत में आयात होने वाली दवाईयों के मार्ग निश्चित किए गए हैं। ये मार्ग हैं –

बंदरगाह :– पूर्वी तट पर चेन्नई, कोलकाता, पश्चिमी तट पर मुंबई, नवा शेवा, कोच्चि, कांडला

एयरपोर्ट :– चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद।

फिर चेन्नई ही क्यों ? चेन्नई इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। इन दवाओं के बिकने का कारण ये है, कि वो व्यापारी जो चीन के लाइसेंसधारी दवा निर्माताओं से दवा खरीदते हैं, उन्हें 5–7% मुनाफा होता है, पर नकली दवा पर 15–20% मुनाफा होता है। ऐसा ही एक आँख खोलने वाला तथ्य है, बिना IMEI क्रमांक के चीनी मोबाइल, जो आतंकी घटनाओं को देखते हुए बेहद खतरनाक हो सकता है। IMEI क्रमांक मोबाइल हैंडसेट में डाली हुई 15 अंकों की संख्या है जो उपयोगकर्ता द्वारा कॉल करने पर ऑपरेटर के नेटवर्क में रिकार्ड हो जाती है, जिससे फोन धारक को ढूँढ़ा जा सकता है। अभी–अभी इनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

❖ ❖ ❖

क्यों नहीं सुधरता पाकिस्तान ?

दुनिया में देशों के पास सेनाएँ हैं, पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है।

पाकिस्तान के बारे में प्रत्येक भारतीय एक बात जानता है कि, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद निर्यात करता है, लेकिन इसका इलाज क्या है, इसको लेकर जनसामान्य से लेकर नीति नियंताओं तक स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती । आजकल पाक में लोकतंत्र और स्थिरता की

आवश्यकता पर यदा कदा बातें होती रहती हैं। ऐतिहासिक तथ्य यह है, कि पाकिस्तान स्थिर रहा हो या अस्थिर, लोकतंत्र रहा हो या तानाशाही, भारत पर हमले हुए हैं, और भारत के विरुद्ध षड़यंत्र चलते रहे हैं। इससे पता चलता है, कि कुछ मूलभूत बात से हम चूक रहे हैं।

नफरत और मजहबी उन्माद के आधार पर बने पाकिस्तान की आज तक कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है। सारी शक्ति सेना के हाथ में है, भले ही जनता की चुनी हुई सरकार राज कर रही है। ISI सेना के हाथ में है, अतः आतंकवाद के मुद्दे पर आप पाक के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशमंत्री या किसी से भी बात कर लें, वो कुछ भी आश्वासन दें, उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि सेना की मर्जी के बिना वे कुछ कर नहीं सकते। दुनिया में देशों के पास सेनाएँ हैं, पर पाकिस्तान में सेना के पास देश है। सेना वहाँ सब कुछ चलाती है, सरकार, उद्योग, परिवहन, आधारभूत ढाँचा, शिक्षा और निवेश। सब पर उसी का नियंत्रण है। राजनीतिज्ञ सेना को नाराज नहीं करते। चुपचाप उतना करते हैं, जितना कहा जाता है। सेना की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले या उसके पर कतरने की कोशिश करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उठा कर बाहर फेंक दिये जाते हैं। प्रेस से लेकर सामाजिक राजनैतिक संगठनों तक जो भी पाकिस्तान के इस असली आका के विरुद्ध आवाज उठाता है, वो या तो मार दिया जाता है या गायब हो जाता है। 26 अगस्त 2011 को पंजाब प्रांत के राज्यपाल रहे सलमान तासीर (जिनकी पाकिस्तान के कुख्यात ईशनिंदा कानून का विरोध करने पर 4 जनवरी 2011 को हत्या कर दी गई) के पुत्र और उद्योगपति शाहबाज तासीर का अपहरण हो गया। कोई सुराग नहीं मिला।

इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ''कानून लागू करने वाले एक उच्चस्तरीय अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शाहबाज का अपहरण गुप्तचर एजेंसियों ने किया है, क्योंकि उन्हें देश के प्रति उनकी 'वफादारी' पर शक था।''

पाकिस्तान में ये आम बात है। आज से दो दशक पहले पाकिस्तान में सैन्य परेड के दौरान एक पत्रकार ने एक टैंक का करीब से फोटो लिया (उस टैंक को पाक निर्मित कहा जाता है) और उस फोटो में पेंट से छिपाया गया 'Made in China' पकड़ में आ गया। फोटो प्रकाशित होने के बाद पत्रकार गायब हो गया। पाक के गैरसरकारी संगठन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुसार ''परवेज मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान जाँच एजेंसियों ने 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का अपहरण किया, और यह सिलसिला आज भी जारी है।'' संस्था की अध्यक्षा आमना जंजुआ के शिक्षाविद पति मसूद जंजुआ मई 2005 से लापता हैं। जंजुआ का दावा है कि उनके पति को सुरक्षा एजेंसियों ने बंदी बना

रखा है।

पाकी सेना का सरकार पर कितना नियंत्रण है, इसका उदाहरण दुनिया ने 26/11 के मुंबई हमले के समय देखा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा कि घटना की जाँच में सहयोग के लिए वे I.S.I. प्रमुख को भारत भेजेंगे, पर जनरल कियानी ने दबाव बनाया और 24 घंटे के अंदर जरदारी अपनी बात से पलट गए।

पाक की भारत नीति पाकी सेना तय करती है।

सब जानते हैं कि 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले में I.S.I. का हाथ था। I.S.I. अर्थात् पाकिस्तान की सेना का ही विस्तार। प्रश्न ये उठता है, कि जब सब ओर से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और I.S.I. की आलोचना हो रही है, तो सेना ने I.S.I. के माध्यम से ये हमला क्यों करवाया ? वास्तव में इससे सबसे ज्यादा फायदा सेना और उसके प्रमुख जनरल कियानी को ही पहुँचने वाला था और पहुँचा भी। हो ये रहा था कि अमेरिका के दबाव में सेना आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही (काफी सीमित) कर रही थी, ये कार्यवाही भी उन आतंकी गुटों के खिलाफ हो रही थी जो या तो I.S.I. के नियंत्रण से बाहर जाना चाह रहे थे, या जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। पर जिहाद की घुट्टी पीकर बड़ी हुई पाकिस्तान की पीढ़ी इससे नाराज थी, कि 'इस्लाम पर हो रहे हमले' में फौज दुश्मनों का साथ दे रही है। उधर अमेरिका और अधिक कार्यवाही कर दबाव डाल रहा था। ~~मुंबई हमले से ध्यान हटाने~~ का सुलझाया हा कुछ बानसं अकि भी।दए।

भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान को अमेरिका को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया, और अमेरिका भारत पर दबाव बनाने लगा कि वो पाकिस्तान के प्रति कठोरता न बरते, और ऐसा हुआ भी। सहायता माँगने के लिए (आर्थिक और सैन्य साजो सामान) पाकिस्तान का मुँह एक बार फिर खुल गया। पाकिस्तान के जनसामान्य में अमेरिकी ड्रोन हमलों और सेना के विरुद्ध उत्पन्न हुआ आक्रोश चिरशत्रु भारत की ओर मुड़ गया।

खाकी और चाँद सितारे का मेल

आज का पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र है। जिसमें खाकी और चाँद सितारा आपस में घुल मिल गये हैं। पाकिस्तान में जिहाद की शिक्षा केवल मदरसों में नहीं दी जाती है। थोड़े कम आक्रामक रूप में सरकारी पाठ्यक्रम भी इसे पढ़ाते हैं। और अधिकांश राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन भी जिहाद और भारत विरोधी घुट्टी जनता को पिलाते हैं। मीडिया भी इसी रंग में रंगा है।

पाकिस्तान में सेना इतनी शक्शिाली कैसे बनी खाकी और चाँद तारे का मेल कैसे हुआ और जिहाद और भारत विरोध कैसे राजनीति की धुरी बन गया ? पाकिस्तान में जनता की चुनी हुई सरकारों को सेना द्वारा पलट दिए जाने का इतिहास रहा है। पहली बार 1951 में ऐसा हुआ। अयूब खान सेनाध्यक्ष बने 1958 आते–आते अयूब खान ने सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। अपनी तानाशाही को उचित सिद्ध करने के लिए अयूब खान ने भारत का हौव्वा खड़ा किया। और कहा कि हमें पाकिस्तान को नेशनल सिक्यूरिटी स्टेट बनाना है। Social Security और Social welfare State (सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेल फेयर स्टेट) की बात नहीं की। 'हिंदू भारत' को पहले से ही शत्रु मानने वाली पाकिस्तान की जनता को सिखाया गया कि जिन हिन्दुओं के कारण हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा उन्हीं हिन्दुओं का राज्य भारत पाकिस्तान को मिटाना चाहता है। हमें उसके विरुद्ध जिहाद करना होगा। इस तरह सेना और इस्लामिक अवधारणा का तारतम्य हुआ। भारत से जंग की तैयारियाँ शुरु की। अमेरिका से मित्रता की गहरी नींव पड़ी। अमेरिका से पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा और सेना के लिए हथियार आने लगे। भारत को फतह करने के लिए पहला लक्ष्य कश्मीर तय हुआ। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अयूब ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए इस्लामिक अवधारणा को तो अपनाया लेकिन मुल्ला मौलवी और इस्लामिक संस्थानों को दूर रखा।

1965 में कश्मीर को हथियाने के लिए अयूब खान ने घुसपैठ करवाई। जो पूर्ण युद्ध में बदल गई। पाकिस्तान बुरी तरह पिटने लगा। अमेरिका और रूस के पास जाकर पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने की गुहार की। ताशकंद में समझौता हुआ। ताशकंद से पाकिस्तान वापस लौटकर हवा उड़ाई गई कि हम लड़ाई जीत गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो जो खुद विदेश मंत्री की हैसियत से ताशकंद वार्ता में शामिल थे। और पाकिस्तान की हार की सच्चाई उन्हें पता थी, ने पाकिस्तान की जनता से राजनैतिक रैलियों में यह कहना शुरु कर दिया कि हमने भारत को हरा दिया था। पर पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों (अयूब खान) ने युद्ध विराम करके और समझौता करके भारत को फायदा पहुँचाया।

भुट्टो की लोकप्रियता बढ़ने लगी और अयूब खान की घटने लगी। 1971 का भारत–पाक युद्ध पाकिस्तान के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ और उसके दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान की जनता के बीच सेना की साख गर्त में पहुँच गई।

'इस्लामी बम' का जन्म

1973 में पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र आया और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने। भुट्टो ने लोकतंत्र और संसदीय तंत्र की बात की पर उसके साथ इस्लाम जोड़ना नहीं भूले। भारत से बदला लेने की बातें की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपना राजनैतिक कद बढ़ाने और पाकिस्तान में अपने पक्ष में उन्माद पैदा करने के लिए भुट्टो ने इस्लामिक बम के रूपमें परमाणु बम की बात की। दुनिया के सारे इस्लामी देशों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान का परमाणु बम सारे इस्लामिक जगत का इस्लामिक बम होगा। भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के मुस्लिम जगत में शोर मचाया कि ईसाई, यहूदी और हिन्दू सभ्यताओं के पास अपने-अपने परमाणु बम हैं। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम जगत के लिए परमाणु बम बनायेगा। पाकिस्तान में एक बार फिर भारत विरोधी जिहादी उन्माद का रंग गहरा होने लगा। और उसमें सऊदी अरब के तेल का पैसा भी जुड़ गया है। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। दुनिया में दो ध्रुव थे अमेरिकी गुट और रूसी गुट, तीसरा गुट खड़ा हुआ था, गुटनिरपेक्ष के नाम से, लेकिन भुट्टो चौथे गुट अर्थात इस्लामिक देशों के गुट की बात कहकर पश्चिम एशिया का माहौल बिगाड़ रहे थे, और परमाणु बम की भी बात कर रहे थे। अमेरिका को पश्चिम एशिया से सस्ता तेल चाहिए था। भुट्टो की बात तूल पकड़ लेती, तो पश्चिम एशिया में उसके हित प्रभावित होते हैं। सी.आई.ए. ने हस्तक्षेप किया, सेना ने भुट्टो की सत्ता उलट दी एक बार फिर पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही आई। जनरल ज़िया-उल-हक का उदय हुआ।

पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद की फैक्ट्री बना

न्यायपालिका के साथ मिलकर ज़िया ने भुट्टो को फाँसी दे दी। मुल्ला, फौज और न्यायपालिका तीनों इकट्ठे हुए। अमेरिका के हितों की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के इस्लामीकरण का नया दौर शुरु हुआ। ज़िया उल हक अपनी तानाशाही को कानूनी रूप देने का रास्ता तलाश रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को निजाम-ए-मुस्तफा (इस्लामिक तंत्र) बनाने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू कर दिए गए। 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया तो ज़िया उल हक की उपयोगिता अमेरिकी गुट के लिए काफी बढ़ गई। सऊदी अरब का पैसा, अमेरिकी हथियार, जिया की सरकार और इस्लाम की पुकार इन सबसे मिलकर तालिबान का जन्म हुआ। सेना और ISI की पकड़ ने गहरी जड़ें जमा ली। पाकिस्तान और सेना के इस्लामीकरण को संवैधानिक जामा पहना दिया गया। ज़िया-उल-हक ने भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध की शुरुआत की। क्योंकि जिया का स्पष्ट मत था कि भारत को सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं है। उन्होंने भारत को एक

बड़ी चोट देने के स्थान पर हजार छोटे घाव(Thousand cut death) देने की नीति बनाई। कश्मीर में उग्रवाद शुरु हुआ, जिसे सारे भारत में फैलाया गया। धीरे-धीरे ISI ने सारे विश्व में जिहादी आतंकवाद से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान वैश्विक इस्लामी आतंकवाद की धुरी बन गया। आज ISI के द्वारा भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में इस्लामिक जिहाद की जो फसल उगाई जा रही है उसके बीज ज़िया उल हक ने ही डाले थे।

निरंतर उलटफेर

अफगानिस्तान में सोवियत रूस के पतन के बाद CIA के लिए ज़िया उल हक की उपयोगिता खत्म हो गई। परमाणु बम के लिए जिया-उल-हक का आग्रह बना हुआ था। ज़िया उल हक गए। पाकिस्तान में एक बार फिर लूला लंगड़ा लोकतंत्र आया। सेना सर्वशक्तिमान थी। सेना ही सारे प्रमुख निर्णय लेती थी। लोकतांत्रिक सरकार का कार्यक्षेत्र स्थानीय निकाय से अधिक नहीं रह गया। अमेरिका से मोलभाव करने का भी तरीका सेना ने विकसित किया। जब अमेरिका से लड़ना होता तो सेना जनता के माध्यम से लड़ती, जैसे अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन, हड़ताल, आगज़नी, मजहबी सभाएँ और जब हथियार पैसा मांगना होता, तब सेना अमेरिका से सीधी बात करती थी। यही सब आज भी जारी है।

हल यही है कि भारत परिस्थितियों का उत्तर मात्र देने के स्थान पर अपने अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करे-

पाकिस्तान में सेना इस्लाम और मुल्ला का जो गठजोड़ बना था, वो आज भी चल रहा है। शासन के मुखौटे बदलते रहते हैं। पाकिस्तान को यदि बदलना है, तो संविधान, सेना और ISI तीनों में नए सिरे से नई व्यवस्था करनी होगी, और पाकिस्तान के समाज को इस्लामिक कट्टरता के दायरे से बाहर लाना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा, कि पाकिस्तान एक असफल राज्य सिद्ध हो चुका है। सिंध, बलूचिस्तान, कराची कोई भी इस्लामाबाद के पंजाबी मुस्लिम प्रभुत्व वाले राजतंत्र से खुश नहीं हैं। ISI समर्थित उग्रवादी गुट, गैर सुन्नी मुस्लिम गुटों विशेष रूप से शियाओं, हजारा, अहमदी और बरेलवी समुदाय को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान अपने दूसरे विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। भारत को आक्रामक रक्षा नीति और पहल करने वाली कूटनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। परिस्थितियों का जवाब देने के स्थान पर परिस्थितियों को उत्पन्न करना होगा। तभी भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पायेगा और धरती के इस सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्से में शांति स्थापित हो सकेगी।

❖ ❖ ❖

देशी रक्षा तकनीक, रक्षा उत्पादन और रक्षा तैयारियाँ– किस राह पर हैं हम

चीन का रक्षा बजट हमसे कई गुना है। वर्ष 1998 से वह उसमें प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि करता आया है। पाकिस्तान पर भारत की सैन्य श्रेष्ठता का अनुपात 1 पर 1.8 था, परंतु अब अमेरिका और चीन से मिल रही सहायता (चीन से रणनीतिक साझेदारी के चलते और अमेरिका से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के नाम पर) से वह 1 पर 1.3 तक आ गया है।

चीन की सैन्य तैयारियाँ हमसे बेहतर हैं, उसका एकमात्र कारण उसका रक्षा बजट हमसे अधिक होना नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। चीनी सेना जो भी सैन्य साज–समान जैसे– लड़ाकू विमान, जहाज पनडुब्बी आदि) प्राप्त करती है, वो हमसे एक तिहाई कीमत का होता है, क्योंकि ये सब वे प्रायः अपने ही देश में तैयार करते है।, जबकि हम उसे बाहर से खरीदने को ही प्राथमिकता देते हैं। रक्षा बजट में से हर साल 1000 से 10,000 करोड़ खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि जिम्मेदार जगहों पर लॉबी बैठी है, जो भारत में बनी हर चीज को ठुकरा देती है। इसका ताजा उदाहरण है, 'तेजस'। यह हमारे द्वारा बनाया हुआ हल्का लड़ाकू विमान है। इसके बारे में पूर्व वाइस एडमिरल रमन पुरी कहते हैं ''मेरे मत में तेजस एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है, जो मिराज–2000 का स्थान ले सकता है।... जब हम एक मिराज 2000 को उन्नत बनाने या सुधार करने (Upgrade) में 200 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो 130 करोड़ की कीमत का स्वदेश निर्मित विमान तेजस का उपयोग क्यों नहीं कर सकते ? इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है।'' और ये सच है। इसका प्रमाण देते कुछ तथ्यों पर गौर करें:–

(1) रूस से हमने गोर्शकोव (विमानवाही पोत) 10,000 करोड़ में 2010 में खरीदना तय किया था, अब हम इसे 2012 में लाऐंगे 20,000 करोड़ से ज्यादा कीमत पर।

(2) जो बम भारत में 870 रु. प्रति नग में बन रहे थे, ठीक उन्हीं बमों को 9000 रु. प्रति नग की कीमत पर खरीदा गया।

(3) अभी रूस से जो गोले 4000 रु. प्रति नग खरीदे जा रहे हैं, उन्हें देश में 800 रु. प्रति नग बनाया जा सकता है। अर्थात् पाँच गुना अधिक पैसा दिया दूसरी ओर हमारे आयुध निर्माणी कर्मियों के पास काम नहीं है।

वास्तव में रूस समेत अनेक पश्चिमी देशों में अपना माल बेचने के लिए खरीददार को व्यक्तिगत कमीशन देना गलत नहीं माना जाता, इसलिए ये सारा गोलमाल वर्षों से जारी है। फिर

जितने माल का सौदा हुआ, उतना आया कि नहीं, इसके हिसाब की चर्चा नहीं होती। गोपनीयता का पर्दा इस भ्रष्टाचार की रक्षा करता है। रक्षा सौदों में बहुत बड़ी लूट जारी है। कई बार गोदामों में आग लग जाती है, और हिसाब–किताब सब स्वाहा हो जाता है। आग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। आयातित माल की गुणवत्ता भी गोपनीय विषय है।

एक और बात ध्यान देने योग्य है कि दूसरे देशों से होने वाले हर बड़े रक्षा सौदे से पहले मीडिया का एक बड़ा वर्ग हवा बनाना शुरु कर देता है, कि सेना के पास हथियारों की, साज समान की भारी कमी है। स्वदेशी तकनीक और उसके विकास पर चर्चा नहीं होती। यही उत्पादन यदि देश में हो तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और सेना को सस्ता सामान। हमारे पास तकनीक विकसित कर सकें ऐसे मस्तिष्कों की कमी नहीं है। हमने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का निर्माण किया है। हमारी युवा पीढ़ी हमारी आवश्यकता की हर चीज बना सकती है। पर उन्हें मौका देने वाला कोई तो चाहिए ही है। सब बाहर से खरीदोगे, तो हमारे यहाँ की प्रतिभाएँ कहाँ जाऐंगी ? और नयी विकसित कैसे होंगी ?

दूसरा पहलू यह है कि आप सीमेंट या स्टील खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, कि एक नहीं तो दूसरा बेचने वाला मिल जाएगा, और ना ही इनकी तकनीक अद्वितीय (Unique) है। आप उच्चस्तरीय रक्षा उत्पादन की बात कर रहे हैं, जहाँ निरंतर बेहतर तकनीक की दरकार होती है, और कोई देश आपको अपनी नवीनतम तकनीक नहीं बेचता। वो दो तीन पीढ़ी पहले की तकनीक आपको बेचता हैं आप हमेशा पीछे रहते हैं, और हमेशा निर्भर रहते हैं।

कल यदि आप चाहें तो नयी तकनीक रातों रात विकसित नहीं कर पाएँगे। हर नयी खोज के पीछे पुराने कामों का अनुभव होता है, लंबे समय से सोच रहे मस्तिष्क होते हैं, और दशकों से विकसित हो रहे संस्थान होते हैं। इन तीनों के बिना आधुनिक तकनीक विकसित नहीं होती, यदि आप आज प्रयास नहीं करेंगे तो आप इन तीनों का विकास कैसे करेंगे–अनुभव, मस्तिष्क और संस्थान।

बहुत सी बातें ऐसी सामने आती हैं, कि अंधेरगर्दी के सिवाय दूसरा शब्द नहीं सूझता। 8 मार्च 2011 की ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) की रिपोर्ट है, कि भारत में टेलीकाम (मोबाइल फोन आदि) का उपयोग करने वालों की संख्या 80 करोड़ से ऊपर पहुँच गई है, और लगातार बढ़ रही है, दुनिया में सबसे तेजी से। मीडिया में बड़ा हल्ला होता है, तालियाँ बजती हैं। पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि टेलीकॉम क्षेत्र में भारत अपने उपयोग के लिए एक स्विच तक नहीं बना रहा है। जबकि सबकुछ हमारे यहाँ बन सकता है और इतना ही नहीं हम उसे खरीद रहे हैं चीन से। जानते हैं इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है ? युद्ध के समय चीन आपका सारा तंत्र ठप्प कर

सकता है। रेल्वे रिजर्वेशन, बिजली वितरण, टेलीफोन मोबाइल और आपके उपग्रहों से आपका संपर्क भी खतरे में आ जाएगा। हम आज टेलीकॉम क्षेत्र में 74% FDI नीति (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, Foreign direct investment) पर चल रहे हैं। आपके पास 80 करोड़ उपभोक्ता हैं, आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम सुरक्षा उपकरण सबके लिए टेलीकॉम की आवश्यकता है, और आप उसका निर्माण नहीं कर रहे हैं। ये सवा अरब की आबादी वाले देश की नीतियाँ हैं, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चाहता है। (हम पनडुब्बी बना सकते हैं, पर अपमानजनक शर्तों पर खरीदना ही पसंद करते हैं।) ये महाशक्ति बनने का पथ नहीं है। महाशक्ति तो छोड़िए अपनी सुरक्षा करते हुए आत्मसम्मान से जीने वालों का भी ये रास्ता नहीं है।

❖❖❖

रक्षा प्रशासनिक ढाँचा–एक प्रश्न ?

सुरक्षा संबंधी मामलों में चिंतन करते समय प्रशासकीय ढाँचा क्या है, यह भी बहुत महत्व की बात है। हमारे यहाँ आज भी रक्षा विभाग का समन्वित प्रमुख नहीं है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के समन्वित विकास और तंत्र के बिना आधुनिक लड़ाई में बढ़त बनाना संभव नहीं है। फिर रक्षा विभाग की नियुक्तियों की बात करें। भारत में रक्षा सचिव हमेशा ऐसा व्यक्ति होता है, जिसका सैन्य क्षेत्र में एक दिन का अनुभव भी नहीं होता। जब नये रक्षा सचिव की नियुक्ति करनी होती है, तो जो भी उपलब्ध वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट होता है, नियुक्त कर दिया जाता है। वो कल तक रेल्वे या वाणिज्य या ऐसा ही कुछ संभाल रहा था, आज उसे रक्षा सचिव बना दिया। अब यदि उसे सेना और सैनिकों की आवश्यकताएँ समझ नहीं आतीं तो उसे दोष क्यों दिया जाए। इसके विपरीत अमेरिका का उदाहरण लें, तो वहाँ रक्षा सचिव (और कभी–कभी राष्ट्रपति भी) को तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त जनरलों या सेना के अन्य अधिकारियों में से चुनने की लंबी परंपरा रही है।

❖❖❖

राजनैतिक षड़यंत्रों और लचर तंत्र की शिकार आतंकरोधी लड़ाई

भारत की जनता बार–बार जिहादी आतंकी हमलों का शिकार हो रही है। आखिर क्यों सरकार उसे सुरक्षा देने में असफल सिद्ध हो रही है ? वास्तव में आतंकवादियों के हौसले बढ़े हुए हैं। कारण है नयी दिल्ली की कमजोर, भ्रमित और राजनीति प्रेरित आतंकरोधी नीति।

वोट बैंक की राजनीति के चलते अफजल गुरु को उसके कृत्य की सजा नहीं दी जा सकती। बाटला हाउस के शहीद पुलिस अधिकारी का अपमान होता है, और आतंकियों से

सहानुभूति दिखाते हुए तथाकथित सेकुलर नेता आँसू बहाते है। क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ के चलते ऐसा ही एक मिथ गढ़ा गया 'हिन्दू आतंकवाद'। क्या वास्तव में कहीं हिंदू आतंकवाद नाम की चीज है ?

राजनैतिक कारणों से यह शब्द उछालकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का राजनीतिकरण किया गया, उसे कमजोर किया गया। जब हम जिहादी आतंकवाद की बात करते हैं, तो उसका अर्थ होता है ।S। द्वारा भारत सहित विश्व के अनेक क्षेत्रों में निर्यात किया जा रहा उग्रवाद। उसका अर्थ होता है, अलकायदा, तालिबान, लश्करे तैय्यबा, जैश–ए–मोहम्मद, हूजी, इंडियन मुजाहिदीन और ऐसे ही सैकड़ों संगठन। ऐसे संगठन जिनसे दुनिया डर रही है, कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार चुराकर किसी महाविनाश को अंजाम न दे दें। क्या ऐसा कोई हिंदू आतंकवाद है ? क्या भारत की रॉ या सीबीआई ऐसा कोई आतंकवाद निर्यात करती हैं ? ये वोटबैंक की राजनीति के लिए सोच समझकर फैलाया गया भ्रम है, जिसने राष्ट्र के मनोबल को तोड़ा है। जब आतंकवादी घटनाओं के संबंध में गिरफ्तारी होती है, तो तुरंत कई ओर से हल्ला शुरु हो जाता है, कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षाबलों का और ऐसे नागरिक जो प्रशासन को सूचना देकर जाँच में सहायता कर सकें दोनों का मनोबल तोड़ा जाता है। वोट बैंक की राजनीति कहाँ तक जा सकती है, इसका ताजा उदाहरण है, वरिष्ठ पत्रकार रहे अज़ीज बर्नी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मामला।

राष्ट्रीय सहारा के तत्कालीन संपादक अज़ीज बर्नी ने एक पुस्तक लिखी ''26/11 आर.एस.एस. की साजिश ?'' इस पुस्तक में मुंबई पर हुए 26/11 हमले को हिंदू संगठनों CIA और मोसाद की साजिश बताया गया। यही नहीं भारत की गुप्तचर एजेंसियों और सुरक्षाबलों को भी इस साजिश से जोड़कर दिखाया। इस पुस्तक का उद्घाटन करने गए दिग्विजय सिंह। सोचने वाली बात यह है, कि इससे किसको लाभ पहुँचा ? अज़ीज बर्नी को जब इस तथ्यहीन पुस्तक के लिए कानूनी नोटिस दिया गया, तो उन्होंने क्षमा याचना की, जो 26 जनवरी को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुई। जब केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार पाकिस्तान से इस जघन्य कांड के आरोपियों को भारत को सौंपने की मांग कर रही थी, तो कांग्रेस के महासचिव ऐसी पुस्तक का विमोचन करने कैसे गए ? दिग्विजय सिंह तो ये बहाना भी नहीं बना सकते कि उक्त पुस्तक उन्होंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि पुस्तक का शीर्षक ही इसके पीछे की दुर्भावना और उसकी सामग्री की झलक दे देता है। एक और बात यह कि जब मुंबई में यह जघन्य कांड चल रहा था, उस समय अज़ीज बर्नी पाकिस्तान के कराची शहर में थे। जाँच की जानी चाहिए कि क्या कर रहे थे ? और उन्होंने ये सब बातें किससे पूछकर लिखीं ? जाँच तो नहीं हुई अभी इतना बताना पर्याप्त होगा कि अज़ीज बर्नी की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के सलाहकार के रूप में कर दी गई है। ये हैं तथाकथित 'हिन्दू आतंकवाद' का सच।

हिंदू आतंकवाद एक ऐसा शिगूफा है जिसके लिए पाकिस्तान बार-बार UPA सरकार को धन्यवाद देता होगा। इसका एक उदाहरण देखें। ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल ने CNN चैनल पर फरीद जकारिया से बात करते हुए 'हिंदू आतंकवाद' की ओर इशारा किया और 26/11 के मुंबई हमले को भारत के अंदर से की गई कार्यवाही (Inside Job) बताया। पाकिस्तानी मीडिया तो अब आतंकवाद संबंधी हर आरोप पर हिंदू आतंकवाद का राग अलापता है। वहीं दूसरी ओर भारत के गृहमंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस पार्टी के दो-दो महासचिव, जिनमें एक कांग्रेस के 'युवराज' भी हैं, भारत से बैठे-बैठे उनके सुर में सुर मिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने संवेदनशील मुद्दे का ऐसा राजनीतिकरण करने वाले आतंकवाद के विरुद्ध कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, समझा जा सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए हमें ताकतवर गुप्तचर तंत्र की आवश्यकता है। पर आज यह देखने में आ रहा है, कि सारा खुफिया तंत्र सरकार ने अपने राजनैतिक विरोधियों, विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, के पीछे लगा रखा है। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की अंकसूची के पीछे परेशान गृहमंत्रालय के पास अभी फुर्सत नहीं है कि वो किसी और मामले पर ध्यान दे सके।

आतंकवाद का सामना करने के सरकारी तौर तरीकों में जो तकनीकि दोष सामने आ रहे हैं वो भी कम गंभीर नहीं हैं। दिल्ली में न्यायालय पर हमला हुआ तो गृहमंत्रालय ने कहा हमें जानकारी थी पुलिस को बता दिया था, अर्थात् ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ दिया। पहली बात ये कि जानकारी कितनी वर्गीकृत (Classified) थी, क्योंकि अनुमान तो बहुत होते हैं। दूसरा दिल्ली पुलिस की चूक थी तो दिल्ली पुलिस भी तो केन्द्रीय गृहमंत्रालय के अंतर्गत आती है।

मुंबई हमले के बारे में भी ऐसी ही बात आई थी। फिर जब आतंकवादी हमला हुआ, तो विशेष कमांडो दस्ते को भेजने में घंटों की देरी हुई। बाद में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कई घोषणाएँ हुईं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। गृहमंत्री ने घोषणा की कि एक सुपर एजेन्सी NIA बनाई जाएगी। नखदंत विहीन और आधारहीन NIA तैयार है, पर कर कुछ नहीं रही है। क्योंकि जिसके बल पर आप आगे बढ़ेंगे जैसे पुलिस, गुप्तचर विभाग वो तो वैसा का वैसा ही है। एक पुलिस का सिपाही जिसके पास स्थानीय संपर्क और नेटवर्क होता है, उसको प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया गया ? स्थानीय पुलिस के सूचना नेटवर्क को सुधारने की क्या योजना बनाई गई ? पिछले पाँच वर्षों से रॉ में नयी भर्तियाँ नहीं हुई हैं। परिणामस्वरूप गुप्तचर व्यवस्था कमजोर हो गई है। पुलिस गुप्तचर विभाग सहित आतंकविरोधी लड़ाई के अगुआ जिम्मेदार लोगों के अराजनीतिकरण की आवश्यकता है। नये पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने में बहुत समय लगेगा। परंतु और भी रास्ते हैं। भारतीय सेना से हर

साल 40,000 उच्च प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी और सैनिक बहुत कम आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी में इन समस्याओं का सीधा अनुभव लिया है। उनका उपयोग हम क्यों नहीं कर सकते।

गुप्तचर विभागों में तालमेल न होना भी विफलता का एक बड़ा कारण है। मुंबई में 13 जुलाई 2011 को हुए बम धमाकों के बाद गृहमंत्री ने बयान दिया कि इसे खुफिया एजेंसियों की विफलता न माना जाए, परंतु वास्तव में यह खुफिया तंत्र की असफलता ही है। देश की सभी खुफिया एजेंसियाँ अपना काम अलग-अलग ढंग से करती हैं। खुफिया सूचना को एकत्र करने और उसे संबंधित विभागों को भेजने की प्रक्रिया में तालमेल न के बराबर है। गृहमंत्रालय की हवाई बातों को छोड़ दें, तो धरातल पर खुफिया संस्थानों जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), एविएशन रिसर्च सेन्टर (ए.आर.सी.), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आई.बी.), नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गनाइजेशन (एन.टी.आर.ओ.), डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी (डी.आई.ए.) आदि अलग-अलग ढंग से बिना तालमेल काम कर रही हैं। आपसी सहयोग तो छोड़ दें, इनमें आपसी प्रतिद्वंदिता काम में बाधा बनी हुई है। मध्यप्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक डी.के. आर्य कहते हैं कि ''हमारे देश के खुफिया तंत्र के अधिकारी आपस में मिलबैठकर जानकारियों को सही वक्त पर साझा नहीं करते। हर व्यक्ति खुद श्रेय लेना चाहता है, ऐसे में नापाक गुट अपनी हरकतों में कामयाब हो जाते हैं।'' एजेंसियों के बीच ही सामंजस्य का अभाव है ऐसा नहीं है। असली कारण मंत्रालयों के बीच ही सामंजस्य का अभाव है। स्पष्ट दिखता है, कि जब कोई आतंकी हमला होता है, तो सरकार छवि बचाने की कवायद और वादे करने में उलझ जाती है। इसकी मिसाल है 26/11 के मुंबई हमले के बाद के वादे। तीन साल हो चुके हैं।

उस समय क्या वादे किए गए थे और उनका क्या हुआ देखिए :-

(1) बहु एजेंसी केन्द्र की स्थापना होगी, जहाँ सभी एजेंसियाँ जानकारी साझा करेंगी और सूचनाएँ देंगी।

वर्तमान स्थिति - शुरु ही नहीं हुआ।

(2) चारों महानगरों में एन.एस.जी. केन्द्र बनेंगे।

वर्तमान स्थिति - केन्द्र बने पर अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं।

(3) खुफिया सूचनाएँ इकट्ठी करने और भेजने के लिए एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड (नेट ग्रिड) बनेगा।

वर्तमान स्थिति - ढाई साल बाद जुलाई 2011 में जाकर गठित हो पाया। काम कब प्रारंभ करेगा पता नहीं।

(4) राज्यों में 'क्विक रिस्पांस' टीम गठित की जाएगी।

वर्तमान स्थिति – सिर्फ महाराष्ट्र में। वह भी धमाकों के समय क्विक रिस्पांस (तत्काल कार्यवाही) नहीं दे पाई।

(5) देशभर में पुलिस थानों को जोड़ने के लिए अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनेगा।

वर्तमान स्थिति – अब तक नहीं बना।

(6) सभी राज्यों के डी.जी.पी., खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों के उच्चाधिकारियों की एक कोर कमेटी बनाई गई जिसकी हर तीन माह में एक बैठक होनी थी।

वर्तमान स्थिति – तीन सालों में सिर्फ एक बैठक हुई।

सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। 26/11 हमले के बाद सुरक्षाकर्मियों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदने का निर्णय लिया गया। 36 करोड़ रु. कीमत की 20,000 जैकेट्स 21 मई 2009 को खरीदी गईं। कुछ ही समय बाद यह आपूर्ति करने वाली कंपनी के मालिक दंपत्ति को गृहमंत्रालय के मध्यम श्रेणी के अधिकारी को इस सौदे के लिए 10 लाख रु. रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस अधिकारी का कार्य इन जैकेट्स की गुणवत्ता तय करना था। खरीद फरोख्त के ये मामले उद्योगपति और अधिकारी के बीच प्रायः ऐसे ही तय होते हैं। निर्माता वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे पूछते हैं कि आप ही बता दें कि हम ''कितनी कीमत कोड कर दें?'' बढ़ी हुई कीमत का पैसा निर्माता और अधिकारी आपस में बाँट लेते हैं।

अमेरिकी और नाटो के अपनी सेनाओं के लिए मानक (Standard) यह है, कि बुलेटप्रूफ जैकेट ऐसा हो कि सैनिकों के अपने हथियार (अर्थात् एकदम निकट से) से चली गोली से भी सुरक्षा दे सकें, परंतु हमारे जवानों की दी जा रही जैकेट्स आतंकवादियों की गोलियों से भी उनकी रक्षा कर पाने में नाकाम सिद्ध हो रही हैं।

अंडरवर्ल्ड और विशेष रूप से दाउद इब्राहिम की आतंकियों से मिलीभगत और इन पर ISI का नियंत्रण की बातें अब मीडिया के माध्यम से आम हो चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड अब हमारी व्यवस्था की कमजोरियों और राजनैतिक भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर अपने काले धंधे के मुनाफे को सफेद करने में जुटा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण 2G घोटाले से जुड़ी एतिसलात कंपनी का है। सीबीआई की पूर्व की रिपोर्ट में एतिसलात कंपनी को दाउद इब्राहिम के माध्यम से ISI के नियंत्रण में बताया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस

बेंच दिया गया। ऐसे ही 2G घोटाले में शामिल दूसरी कंपनी 'टेलीनॉर' जिसके संबंध चीन की खुफिया एजेंसी से होने की बात सामने आ रही है, उसे भी नियम कानून किनारे करके स्पेक्ट्रम बेचा गया। यदि ये घोटाला नहीं खुलता तो आपकी हर बात ISI और चीन की खुफिया एजेंसी MSS सुन रहे होते। इसमें देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारियाँ भी होतीं। गृहमंत्रालय जानकारी होते हुए आँखें मूंदे रहा। धनलिप्सा जब इस तरह देश की सुरक्षा पर हावी हो, तो आप किस भविष्य की उम्मीद करेंगे ?

अंडरवर्ल्ड का पैसा मॉरीशस, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात के हवाला रैकेट के माध्यम से देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास संबंधी नीतियों तक अपनी पहुँच बना चुका है।

आम भारतीय के सुरक्षित जीवन पर जो ग्रहण लगे हैं, उनमें से कुछ की ही चर्चा यहाँ की गई है।

❖ ❖ ❖

बंग्लादेशी घुसपैठ : भारत के सीमा प्रांतों को निगलने का षड़यंत्र

1971 ई. में भारत–पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप तकरीबन 16 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी हिन्दुस्थान आए और भाषाई एवं मजहबी संबंधों के आधार पर भारतीय समाज के बीच शरणागत हुए। इन नवागत शरणार्थियों में लगभग 19 हजार शरणार्थी हिन्दू थे। पर सरकार ने इनकी कोई सूची नहीं बनाई और न ही मीडिया ने इस संदर्भ में भारतीय हितों के भविष्य की चिंता की। नतीजतन तमाम शरणार्थी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और असम तक फैल गए।

'पूर्वी पाकिस्तान' का इलाका जब 7 दिसम्बर, 1971 ई. को स्वतंत्र हुआ और बंगलादेश के रूप में विश्व के नक्शे पर उभरा तो 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिमटा 6 करोड़ 50 लाख आबादी वाला अनपढ़, गरीब और मुस्लिम देश था। आकार में भारत के 25वें भाग के बराबर। इस देश की आबादी में वृद्धि की रफ्तार भी एशियाई देशों में सबसे तेज है। इस समय बंगलादेश की आबादी 12 करोड़ है और एक सरकारी रपट के अनुसार सन् 2017 तक 24 करोड़ हो जाएगी। वहां आबादी के अनुपात में उपजाऊ कृषि भूमि और अन्य संसाधनों का घोर अभाव है। वहां की बढ़ती हुई आबादी के दबाव का परिणाम यह है कि 1971 ई. से 1999 ई. तक तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख बंगलादेशी घुसपैठिए भारत आ गए और यहां भाषाई एवं मजहबी संपर्क के माध्यम से उन लोगों में जा मिले जो युद्ध के परिणामस्वरूप शरणार्थी बनकर आए थे। भारत में बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या लगभग 2 करोड़ है, जो मुख्यतया असम के 23 में से 10 जिलों को मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बनाने के

बाद पश्चिम बंगाल के 56 चुनाव क्षेत्रों में निर्णायक मुस्लिम आवाज बन चुकी है।

प्राप्त सूचनाओं और नवीन शोध-पत्रों के अनुसार बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हिन्दुस्थान के दूसरे विभाजन की योजना पर काम कर रहे हैं। उनके भावी देश का कल्पित नाम है 'मुस्लिम बंग भूमि', जो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के कुछ क्षेत्रों पर आधारित होगा और अंततः बंगलादेश में समाहित हो जाएगा। 'इज़ इंडिया गोइंग इस्लामिक' पुस्तक के लेखक और अवकाश प्राप्त आई.पी.एस. अधिकारी बलजीत राय के अनुसार बंगलादेशी बुद्धिजीवियों ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा को बंगलादेश की बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के रहने के लिए उपयुक्त करार दिया है और जो भारत के इन पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जे की नीति भी बना चुके हैं।

बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं को उनके घरों और जमीनों से निकाल भगाया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया, लेकिन मीडिया ने कभी इसकी छानबीन नहीं की। कांग्रेस तथा माकपा ने उन्हें अपना वोट बैंक बनाने के लिए खुली छूट ही नहीं दी, बल्कि राशन कार्ड जारी किया और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज करके उन्हें भारत की स्थायी नागरिकता भी दे दी।

स्वयं बंगलादेशी संवाददाताओं ने स्वीकार किया है कि आज भी प्रतिदिन 500 से 1000 बंगलादेशी छोटे-छोटे समूहों में 2,145 किलोमीटर लंबी और खुली हुई सीमा रेखा लांघकर भारत में घुसते हैं। ये घुसपैठिए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं इसके प्रमाण भी हैं।

हिन्दुस्थान की जनता और सरकार हालांकि बंगलादेश की सहयोगी रही है और उसे एक देश के रूप में स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है, लेकिन बंगलादेश की वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने हिन्दुस्थान की मित्रता का अनादर और अपमान किया है। ऐसी स्थिति में बंगलादेश की सरकार और वहाँ से घुस आए बंगलादेशी नागरिकों से वफादारी की उम्मीद करने से पहले हमें उसके साथ 30 वर्ष पुराने रिश्ते की समीक्षा करनी होगी, तभी हम जान पाएँगे कि भारत ने जिन लोगों को सड़क से उठाकर एक स्वतंत्र देश का मालिक बना दिया, वे हमारे मित्र हैं या शत्रु।

यद्यपि बंगलादेशी शरणार्थियों को वापस भेजने की मांग 1975 से ही हो रही है, लेकिन भारतीय मीडिया के एक तबके ने इस मांग को नकार कर उलटे उनके लिए पुनर्वास, सरकारी सेवा में आरक्षण और स्थायी शिविरों की स्थापना की तीन सूत्रीय मांग का समर्थन किया।

1964–65 में ई. नायके–शास्त्री समझौते के तहत 31 दिसम्बर, 1965 ई. से 28 मार्च, 1971 ई. तक भारत आए शरणार्थियों के अलावा उन सभी को वापस चले जाना चाहिए, जो हिन्दुस्थान के नागरिक नहीं हो सके हैं। 1980 में भूपल चौधरी घोष ने शरणार्थियों के पुनर्वास की मांग लेकर आन्दोलन शुरू किया और पश्चिम बंगाल में रह रहे 2 लाख 19 हजार बंगलादेशी शरणार्थियों के वापस 'नहीं' जाने की घोषणा जब यूथ सर्विसेज के मंत्री कान्ति विश्वास ने की तो अंततः यह तय किया गया कि 38 हजार हिन्दू शरणार्थी यहां रह जाऐंगे और शेष मुस्लिम शरणार्थी वापस चले जाऐंगे। मगर तत्कालीन इरशाद सरकार ने इस शर्त को मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह म्यांमार से बंगलादेश पहुँचे रोहिंगिया मुसलमानों को बंदूक की नोंक पर वापस भेजने की कार्यवाही कर रहे थे। 22 सितम्बर, 1992 को उन्हीं के रास्ते पर चलकर वहां की सरकार ने 32,000 रोहिंगिया शरणार्थियों को बंदूक दिखाकर बाहर निकाला। यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फार रिफ्यूजीज (यू.एन.एच.सी.आर.) ने जब मानवीय अधिकारों के संदर्भ में बंगलादेश सरकार को इंसानियत की अदालत में खड़ा किया तो बंगलादेश की सरकार ने और ज्यादा उग्र रवैया अपनाते हुए स्वयं को 22 दिसम्बर, 1992 के दिन पुनर्वास प्रक्रिया से अलग कर लिया। बाद में राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने बंगलादेश को इस कुकृत्य के लिए उसे फटकार लगाई तो वह मई 1993 ई. में पुनः सक्रिय हुआ। लेकिन दक्षिण एशिया में शरणार्थियों के कारण स्वदेशी नागरिकों का जीना हराम हो चुका है, विशेष रूप से हिन्दुस्थान बंगलादेशी घुसपैठियों की निरंतर आपराधिक गतिविधियों, उनकी बढ़ती हुई आबादी और आतंक से त्रस्त हैं। भारत की अखंडता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए एक ऐसा टाइम बम है, जो फटने का इंतजार कर रहा है।

❖ ❖ ❖

असम का तेजी से होता बांग्लादेशीकरण

1991–2001 के बीच असम के छह जिले मुस्लिम बहुल हुए

गत वर्षों से विदेशी मिशनरी पूवोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. असम के विद्रोही गुट उल्फा के साथ मिलकर हिन्दी भाषी भारतीयों पर आक्रमण तो करवा ही रही है, दूसरी तरफ नागा उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड की सहायता से मणिपुर, नागालैण्ड और अरुणाचल में भी अलगाववाद फैला रही है।

उल्फा काफी समय से बिहार एवं उत्तरप्रदेश से असम में रोजी–रोटी कमाने गए लोगों को अपना निशाना बना रही है। हिन्दीभाषी इलाकों में आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं। इस कारण असम से हिन्दीभाषी लोग पलायन भी कर रहे हैं। श्रमिकों की भरपाई षड़यंत्र के अनुसार बंगलादेशी मुसलमानों से की जा रही है। और देखते–देखते असम में मुसलमानों की जनसंख्या में जबरदस्त बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

असम में सन् 1991 से 2001 तक दस वर्ष में मुसलमानों की जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मुस्लिमों की सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी निचले असम के नगांव जिले में हुई है। वहां मुस्लिमों की संख्या में 2,86,954 की वृद्धि हुई हैं ध्यान रहे, यह केवल एक जिले की बात है। आज असम के 6 जिलों में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से अधिक है। वे जिले हैं 1. धुबरी (हिन्दू– 4,05,665 और मुस्लिम 12,16,455) 2. ग्वालपारा (हिन्दू– 3,14,157 और मुस्लिम 4,41,516) 3. बरपेटा (हिन्दू– 6,62,066 और मुस्लिम 9,77,943) 4. नगांव (हिन्दू– 11,06,354 और मुस्लिम 11,80,267) 5. करीमगंज (हिन्दू– 4,70,708 और मुस्लिम 5,27,214) 6. हैलाकाण्डी (हिन्दू– 2,23,191 और मुस्लिम 3,12,849)।

वोट बैंक राजनीति के कारण कई सेकुलर दल बंगलादेशी मुसलमानों को असम के निवासी घोषित करने वाले सरकारी कागजात उपलब्ध करा रहे हैं और राज्य सरकार यह सब आँखे बन्द करके देख रही है। बंगलादेशी घुसपैठियों का पता चलने पर वहां की सरकार सोती रहती है और उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होती। असम में मुसलमानों की अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी से वहां रह रहीं जनजातियों और हिन्दू समुदाय पर खतरा मंडराने लगा है। असम के मुस्लिम बहुल जिलों में तेजी से अलगाव भड़क रहा है।

हिन्दुओं के धार्मिक स्थानों पर भी कब्जे हो रहे हैं। बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या के कारण असम के हिन्दू समाज के धार्मिक स्थलों और सत्रों (वैष्णव मंदिर) का अस्तित्व संकट में है। आज असम में 814 सत्रों की 1,080 बीघा जमीन पर मुस्लिम तत्वों ने जबरन कब्जा किया हुआ है।

यूं कहने के लिए राज्य सरकार ने सत्रों के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण शुरु कर दिया है। देखना यह है कि राज्य सरकार वैष्णव सत्रों की रक्षा में कितनी गंभीरता दिखाती है। मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती आबादी के आंकड़े चौकाने वाले हैं। अभी कुल 6 जिले ही मुस्लिमबहुल बने हैं, और सरकार यूं ही सोती रही तो विधानसभा में बंगलादेशी घुसपैठिए ही अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे और सरकार पर उनका ही कब्जा हो जाएगा।

❖ ❖ ❖

असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र

जिला	हिन्दुओं की संख्या	मुसलमानों की संख्या
धुबरी	4,05,665	12,16,455
ग्वालपारा	3,14,157	4,41,516
बरपेटा	6,62,066	9,77,943
नगांव	11,06,354	11,80,267
करीमगंज	4,70,708	5,27,214
हैलाकाण्डी	2,23,191	3,12,849

सन् 1991–2001 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ोत्तरी

	जिला	इतनी बढ़ी संख्या
1.	धुबरी	2,77,666
2.	कोकराझार	29,640
3.	बोंगईगांव	84,180
4.	ग्वालपारा	1,06,241
5.	बरपेटा	2,00,969
6.	नलबाड़ी	51,189
7.	कामरूप	1,57,458
8.	दरांग	19,335
9.	सोनितपुर	78,219
10.	लखीमपुर	34,415
11.	धेमाजी	3,389
12.	मोरीगांव	79,563

❖ ❖ ❖

पूज्य सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी का उद्‌बोधन

विजया दशमी महोत्सव युगाब्द ५११३
गुरुवार दिनांक ६ अक्टूबर २०११, नागपुर
(उद्‌बोधन की संक्षिप्त प्रस्तुति)

– 86 वर्ष पूर्व विजयादशमी के दिन रा.स्व.सं. का प्रारंभ हुआ।

– संघ निर्माता डॉ. हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। उनके समय देश की स्वतंत्रता और उत्थान के लिए चल रहे अनेक उपक्रमों के वे सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता थे।

– अपने समृद्ध अनुभव एवं अनेक स्वनामधन्य महापुरुषों के साथ हुई चर्चाओं में से एक सर्वमान्य निष्कर्ष उनके हाथ आया जिसकी घोषणा उस समय के एवं आज के सभी महानुभाव अपने-अपने शब्दों में करते आए हैं, कर रहे हैं। देश और दुनिया की वर्तमान स्थिति का तटस्थ विश्लेषण भी हम सबको एक बार उसी निष्कर्ष पर लाता है।

– विश्व के क्रियाकलाप अपने स्वार्थों का पोषण कर सके ऐसी चेष्टा समर्थ देश करते आये हैं। विश्व के अनेक देशों में हो रही हलचलें इस ओर इशारा करती हैं। विश्व पर प्रभुत्व की आकांक्षा को रखकर चीन अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। इस हलचल से हम चाहकर भी अछूते नही रह सकते।

– हम सारी वसुधा को अपना कुटुम्ब मानते हैं, इस दिशा व दृष्टि को कायम रखते हुए हमें अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, प्रतिष्ठा व सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना होगा, और विश्व में विश्वास व सहयोग का वातावरण बनाने के लिए समर्थ होना पड़ेगा।

– हमारे पड़ोसी व विशेषतः दक्षिण पूर्व एशिया से हमारा सीधा सांस्कृतिक संबंध है आर्थिक हित भी समान हैं, और हमारी वहाँ स्वीकार्यता भी है। अतः हमें उनसे अपने आर्थिक, राजनयिक संबंध दृढ़ करने चाहिए। साथ ही नेपाल में स्थिरता व भारत अनुकूल वातावरण बने, तथा श्रीलंका में तमिल नागरिकों की त्रासदी समाप्त हो ऐसी हमारी पहल होना चाहिए।

– बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ तथा शस्त्र, पशु धन, नकली नोट, अथवा नशीली दवाओं की तस्करी बंद हो कर वहाँ हमारे अनुकूल वातावरण बने यह हमें देखना होगा।

– तिब्बत एवं भारत सहित विश्व के अनेक देशों में बसने वाले तिब्बतियों की भावनाओं को वाणी मिले, उनके मानवाधिकार, आस्था, परंपरा सुरक्षित रहे। और वे स्वाभिमानपूर्वक अपनी भूमि में जी सकें, ऐसी उनकी सहायता करनी होगी।

– एशिया में अपना स्वार्थ साधने एवं प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण जल एवं थल दोनों ओर से कर रहा है। पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से उसके तार जुड़ गए हैं। 1962 में हम चीन की धूर्त कूट समरनीति और अपनी ही स्वप्नरंजित मानसिकता का शिकार हो चुके हैं। अतः हमें चीन से पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा आर्थिक संबंधों की परंपरा को बनाते हुए भी सजग रहने एवं सामरिक बल अर्जित करने और पर्याप्त वैश्विक समर्थन जुटाने की आवश्यकता है।

– पाक अधिकृत कश्मीर से 6 देशों की सीमाएँ मिलती हैं। उसके इस महत्व को न समझते हुए हमने उसे आक्रमण का शिकार होने दिया। वास्तव में पाकिस्तान का संविधान और पाक अधिकृत कश्मीर का सर्वोच्च न्यायालय भी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का अंग नहीं मानता।

– कश्मीर की समस्या केवल राजनैतिक समस्या नहीं है। बल्कि विदेश प्रेरित आतंकवाद व कट्टरपंथी मौलवाद द्वारा निर्मित आक्रमण की और हमारी ढुलमुल नीति की समस्या है।

– 1947–48 में विस्थापित और भारतभक्त कश्मीरी हिन्दुओं को फिर से अपनी जन्मभूमि में बसाने की नीति होनी चाहिए, और जम्मू तथा लद्दाख के साथ किया जा रहा भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। धारा 370 खत्म होनी चहिए।

– कश्मीर में 1953 के पूर्व की स्थिति पर लौटने की अलगाववादी साजिश को समाप्त करना चाहिए।

– संसद द्वारा 1994 में पारित प्रस्ताव 'गुलाम कश्मीर को भारत में वापस लाना ही कश्मीर की शेष बची समस्या है' यह संवाद की दिशा होनी चाहिए।

– उत्तर पूर्वांचल की समस्याओं की मुक्ति के लिए राजनैतिक जगत को जानकारी, अध्ययन और वहाँ की जनता की वेदना को समझना अनिवार्य है।

– केन्द्र व राज्य अपनी वार्ताओं से मृतप्राय उग्रवादी गुटों को संजीवनी प्रदान करने में लगे हैं। मिजोरम की रियांग जाति अपने संपूर्ण विलोप का सामना कर रही है।

– असम में बंगलादेश से निरंतर घुसपैठ हो रही है। अधूरा सतही अध्ययन, जनता की संवेदना–वेदना के प्रति उदासीनता, स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव और हर बात को राजनैतिक लाभ–हानि के तराजू में तौलने की आदत ने उत्तर पूर्वांचल की समस्याओं को उलझा दिया है।

– गृहमंत्री द्वारा नक्सली आतंकवाद को सब आतंकवादों में खतरनाक बताना विचित्र बात है। क्या आतंकवाद के भी कम और अधिक खतरनाक प्रकार होते हैं।, और यदि ऐसा है भी तो एक राज्य सरकार को जिस व्यक्ति पर ऐसे ''अधिक खतरनाक'' आतंकवाद से संबंध रखने का संदेह है। उसे केन्द्र ने योजना आयोग की समिति में स्थान कैसे दिया।

– भ्रामक व देश की जड़ें खोदने वाले विचारों को प्रश्रय देने का परिणाम है, कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों और आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु की फाँसी को रद्द करने की मांग को राजनैतिक प्रश्रय मिलता है।

– अपने देश के आर्थिक तंत्र के लिए पश्चिम का अपूर्ण व असफल आर्थिक विचार उचित नहीं, छहः दशकों से हम परानुक्रमण में लगे हैं। हमें अपनी जीवन दृष्टि के आधार पर जनता की आवश्यकता के अनुरूप प्रगति और समृद्धि के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाला अपना विशिष्ट विकास पथ खोजना पड़ेगा।

– सांसदों और विधायकों के वेतन बढ़ रहे हैं। गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। और गरीब की परिभाषा पर ही विवाद हो रहा है।

– सेज (SEZ) के नाम पर कृषि भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण एवं विरोध करने वाले किसानों पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं।

– ऊर्जा के नवीनीकृत स्त्रोतों को छोड़कर पश्चिम जिसका त्याग कर रहा है ऐसी महंगी आण्विक ऊर्जा को अपने देश में लाने के लिए हम तुले हैं। विदेशी निवेश को आमंत्रित कर अपने खुदरा व्यापारियों के लिए हम संकट खड़ा कर रहे हैं।

– बच्चों की महंगी शिक्षा और परिवार के पालन–पोषण में जी रहा आम आदमी काले धन को वापस लाने में की जा रही आनाकानी, ढिलाई व विलंब को देख रहा है।

– जन मन में दीर्घकाल से संचित असंतोष ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के रूप में फूट चुका है। काले धन की वापसी, भ्रष्टाचार निरोधक कठोर कानून और उसका कड़ाई से अमल, उस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री सहित सभी उच्च पदस्थों को समावेश आदि जनता के मुद्दे बन गए हैं।

– भ्रष्टाचार के मामलों में ज्ञात–अज्ञात बड़े सूत्रधार सुखपूर्वक स्वतंत्र घूम रहे हैं। सफलता अभी दूर है। अतः इस लंबी लड़ाई में सफल होने के लिए आंदोलन करने वाली सभी छोटी बड़ी धाराओं को मतभेदों को भूलकर एकत्र होना पड़ेगा।

– श्रेय बटोरन में लगी संदिग्ध पृष्ठभूमियों वाली शक्तियों से दूर रहना चाहिए। वंदे मातरम्, भारत माता आदि राष्ट्रीय संकेतों को भ्रमित दृष्टि अथवा सस्ती लोकप्रियता के लिए नकारना यह किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में स्वीकार्य नहीं है।

– संघ के स्वयंसेवक भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले सभी आंदोलनों में सम्मान अथवा श्रेय की अपेक्षा छोड़कर स्वभावतः लगे ही हैं।

– कानून के अतिरिक्त भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्थाओं में भी मूलगामी

परिवर्तन लाने होंगे । पारदर्शी एवं जनाभिमुख प्रशासन, संस्कारों का वातावरण, धन, बल व अपराधमुक्त चुनाव जनता का सही प्रतिनिधित्व सुसह्य कर प्रणाली और व्यापारीकरण से मुक्त संस्कारदायी शिक्षा आज की आवश्यकता है।

– सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में सामाजिक, दायित्वबोध, विशुद्ध चरित्र सेवा और परोपकार के मूल्यों का संवर्धन और ऐसे आचरण के उदाहरणों के बिना भ्रष्टाचार का निर्मूलन असंभव है। इसी मूलगामी महत्वपूर्ण कार्य में प्रेरित होकर संघ अपना कार्य कर रहा है।

– देश की एकता, सामाजिक सद्भाव और संविधान इन तीनों का ही विपरीत एक नया प्रस्तावित कानून (सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक) राष्ट्रीय एकता परिषद ने प्रस्तुत किया है। इसे तैयार करने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का संवैधानिक स्थान व अधिकार क्या है ? इस परिषद की अध्यक्षा सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल की भी अध्यक्षा हैं। हमारे देश को कौन चला रहा है ?

– यह प्रस्तावित विधेयक संविधान की मूल भावना के विपरीत है । राज्य सरकार से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी को कठपुतली बनाये रखना, मात्र आरोपित होने पर किसी व्यक्ति और उससे संबंधित संस्था या सरकार को उनके प्रमुखों सहित दोषी मानकर उन पर सब प्रकार की कार्यवाही करना अंधेरनगरी में शोभा देने वाला न्याय है।

– इसमें मानसिक कपट जैसे काल्पनिक अपराधों का विचित्र मंडन है। न्याय, प्रजातंत्र, संविधान आदि की अवहेलना करने वाला और दो नागरिकों में भेद करने वाला यह विधेयक क्या विचार करने योग्य है ? संसद व सरकार को इसे सिरे से खारिज करते हुए किसी भी स्वरूप में आने ही नहीं देना चाहिए।

– दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव तथा स्पष्ट व निर्भय राष्ट्रीय दृष्टि की अनुपस्थिति से उपजी हतबलता, ढुलमुल नीति, दब्बूपन, अपनी जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति स्वार्थग्रस्त राजनीति समाज में केवल निराशा व अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर रही है। राष्ट्र जीवन के सभी अंगों में परकीय प्रवृत्ति की आक्रामक व घातक घुसपैठ को रोककर संपूर्ण राष्ट्र को सशक्त व समरस बनाकर चुनौतियों को मात देते हुए वैभव पथ पर आगे बढ़ाने का दायित्व अब समाज को ही सहन करना होगा।

– सत्य की विजय के प्रति पूर्ण आशवस्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्भय चित्त से निरंतर पुरुषार्थ के कर्त्तव्य पथ पर संपूर्ण समाज को साथ जोड़कर चलें। हमारी विजय निश्चित है।

राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा।
संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा ।।

❖ ❖ ❖

सागर की ओर से चीनी खतरा

©2008 Google - Map data ©2008 Tele Atlas, ZENRIN,

DTN News ~ Defense Technology News

DTN News - PAKISTAN DEFENSE NEWS: Pakistan US Relations Downhill - China Relation Uphill

DTN News ~ Defense-Technology News

DTN News - JIHAD & TERRORISM REPORTS: Pakistani Military Officers' Links With Jihadist Organizations

DTN News ~ Defense-Technology News

DTN News - CHINA DEFENSE NEWS: China Sets Up Militar Cyber-Warfare Team ~ Report

TIME
Nuclear Terror For Sale
Once we feared thugs like Carlos the Jackal. Now no one knows who might buy smuggled plutonium—and hold the world hostage
IACSP
://WEAPONS OF_MAS
Weapons of Mass Disruption:
The International Spy Museum's Cyber Warfare Gallery
Spies, Terrorists and Criminals Can Turn Power Lines into

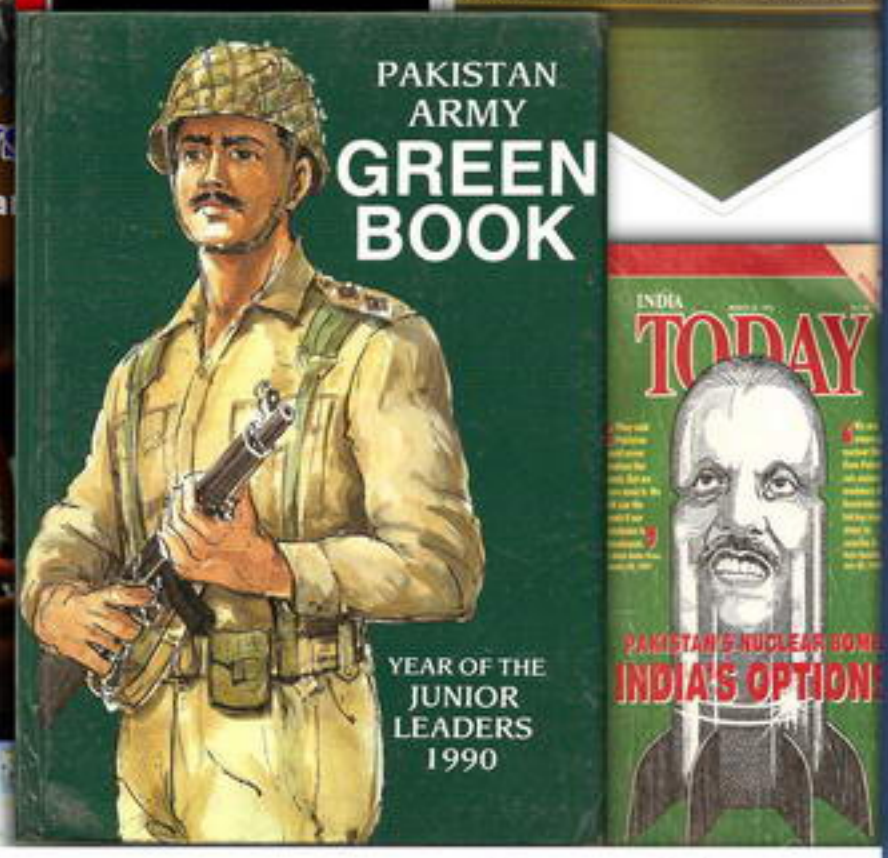

Chinese army in control of much of PoK, says expert

मुद्रक - श्रीराम ऑफसेट,
राइट टाउन, जबलपुर, ०७६१-२३१०१७६
(व्यक्तिगत उपयोग हेतु)

प्रकाशक - प्रचार विभाग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकोशल,
केशव कुटी राइट टाउन, जबलपुर, ०७६१-२४०१६८६

The storm over China's denial of a visa to an Indian general serving in Jammu & Kashmir may be only a "diversionary sideshow" compared

Clearly, China has upped the stakes over Arunachal, but now Kashmir is rising again to

to 3

Chinese army officials

Reacting strongly to China's refusal to grant a visa to Lt